सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 337, नई दिल्ली । गुरुवार, 13 फरवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 दिल्ली से 23 मार्च से आरंभ धर्म पद यात्रा में शामिल होकर....
06 परीक्षा फोबिया- कारण और उपचार
08 3 डिब्बे पटरी से उतरे, मालगाड़ी दीवार तोड़कर बस्ती में घुसी

प्रवर्तन शाखा दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने लिया हरिसत में

संजय बाटला

प्रवर्तन शाखा दिल्ली परिवहन विभाग हमेशा से सुर्खियों मे रहा हैं परंतु उसके बावजूद कभी भी सुधरा नहीं। प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठती रही है, यहां तक की कई वर्षों से तो इनकी कार्यशैली के खिलाफ बीजेपी ही आवाज उठाती रही है। किसी भी मुद्दे में इनकी छवि कभी भी साफ नहीं रही है। **आपकी जानकारी के लिए बता दें पूर्व में उपराज्यपाल के आदेश पर वन मैन इंक्वायरी बैठाई गई थी और उसकी रिपोर्ट आने के बाद से दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा को रात में चालान काटने और नगद चालान पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी।** लेकिन पूर्व में परिवहन आयुक्त पद पर कार्यरत और तत्काल में उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेट्री पद पर आसीन आईएएस अधिकारी आशीष कुंद्रा ने बिना पूर्ण जांच के फिर से प्रवर्तन शाखा दिल्ली परिवहन विभाग को रात में चालान करने की छुट दे दी थी। उसी दिन से लगातार प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आवाजें तेज हो गई थीं पर आम आदमी पार्टी सरकार या परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। **आप की जानकारी के लिए बता दें की प्रवर्तन शाखा में बिना आर.आर. लागू किए परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा अधिकारियों को पदोन्नति देने की शिकायतें होती रही है** पर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। 11 फरवरी 2025 को दल्लि में आम आदमी पार्टी सरकार जाने के बाद सीबीआई द्वारा दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और घूस के आरोप में हिरासत में लिया गया. आम आदमी पार्टी सरकार के जाने के बाद सीबीआई की यह पहली बड़ी कार्रवाई है।

1. परिवहन विभाग प्रवर्तन शाखा के अफसर भ्रष्टाचार और घूसखोरी में पकड़े गए,
2. दिल्ली से लेकर गुड़गांव बॉर्डर इलाके में घूस लेने का इन पर आरोप,
3. परिवहन विभाग दल्लि सरकार के अंतर्गत आता है।

दल्लि में परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों / कर्मचारियों को आम बोलचाल की भाषा में '5 नंबर की पुलिस' कहा जाता है. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई को शकियतें मिल रही थीं कि दिल्ली से लेकर गुड़गांव बॉर्डर इलाके में लोग घूस ले रहे हैं और साथ ही शिकायत कर्ताओं द्वारा कई तरह की जानकारियों को भी उपलब्ध करवाई इसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई की।

बीजेपी लगाती रही है आरोप

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी कुछ ही देर में इसके बारे में जानकारी शेयर करेगी। परिवहन विभाग दल्लि सरकार के अंदर आता है और बीजेपी के नेता कई बार आरोप लगा चुके हैं की दिल्ली के परिवहन विभाग में घूसखोरी चल रही है। हालांकि बीजेपी इसके पीछे आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराती रही हैं और उनके नेताओं को निशाना बनाते रहे हैं।

सीबीआई की माने तो चुनाव नतीजों के बाद से ही राडार पर थे यह अधिकारी सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद से ही सीबीआई के राडार पर थे यह अधकिारी। तब से इनकी ट्रैकिंग की जा रही थी और हिरासत में लिया गया। सीबीआई की माने तो जल्द ही इनसे कुछ और बड़े राज खुलने की उम्मीद हैं। **ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है ऽऽ अगर सही दृष्टि से जांच हुई तो कई बड़े आला अधिकारियों के साथ नेताओं के भी नाम जनता के सामने आयेंगे।**

परिवहन विभाग के रेफ्रेशर कोर्स में दुर्घटनाओं से बचाव के गुर सीख रहे वाहन चालक

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। परिवहन विभाग लगातार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा माह का आयोजन करता है. तमाम तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए कार्रवाई की जाती है, लेकिन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित हो पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर दुर्घटनाओं का आंकड़ा घटने के बजाय बढ़ गया है, उन्हीं जिलों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है. दुर्घटनाओं के लिए ज्यादा दूरी तक और लंबे समय के लिए वाहन का संचालन करने वाले चालकों को भी जिम्मेदार माना जाता है. इसीलिए अब ड्राइवरों को ड्राइविंग के गुर सिखाए जा रहे हैं. साथ ही रिफ्रेशर कोर्स भी कराया जा रहा है.उत्तर प्रदेश सड़क हादसों के मामले में देश में पहले स्थान पर है. सड़क दुर्घटनाओं पर तमाम प्रयासों के बाद भी लगाम नहीं लग पा रही है. टारगेट सेट किया गया है कि दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाना है. सड़क सुरक्षा फंड से तमाम सारे कार्यक्रम जनता को जागरूक करने के लिए आयोजित करने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं जो चिंता का सबब बन रही हैं. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके इसके लिए चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फिटनेस सेन्टर पर अपने वाहनों की फिटनेस कराने के लिए आने वाले वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया. इसमें उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने के लिए यातायात के नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में अवगत कराया गया. वाहन की फिटनेस के सन्दर्भ में फिटनेस सेंटर के इंस्ट्रक्टर की ओर से प्रमुख रूप से ध्यान में रखने वाली बातों को भी साझा किया गया. चालकों को वाहन चलाते समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की अपील की गई।

फिटनेस सेंटर के इंस्ट्रक्टर नितेश सिंह ने वाहनों में क्लच, गियर और ब्रेक का किस प्रकार से भौतिक रूप से परीक्षण कर किसी भी दुर्घटना से बचने के उपायों के बारे में भी अवगत कराया गया. इस अवसर पर फिटनेस सेन्टर प्रभारी आरआई विष्णु कुमार, सेन्टर प्रभारी, आकाश सिंह, इंस्ट्रक्टर नितेश सिंह और वाहन चालक मौजूद रहे।

दिल्ली परिवहन विभाग ने बदले वाहन जब्ती के नियम, 30 दिन में रिलीज कराएं गाड़ी, वरना बन जाएगी कबाड़

दिल्ली में परिवहन विभाग ने वाहनों की जब्ती और रिलीज करने के नियमों में बदलाव किया है। जानें क्या है नया नियम...

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने पार्किंग और प्रबंधन नियमावली 2019 में जब्त वाहनों पर कार्रवाई के नियमों में बदलाव किया है। इसको लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए वाहनों को न छुड़ाने की वजह से बढ़ते वाहनों के स्क्रैप को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

नए नियमों के अनुसार, अगर जब्त किए वाहनों को उनके मालिकों द्वारा नहीं छुड़ाया जाता है, तो स्क्रैप कर दिया जाएगा या फिर सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जाएगा। दरअसल, दिल्ली में अवैध पार्किंग या सड़क किनारे गाड़ियों को खड़ा करने पर उसे जब्त कर लिया जाता है।

अब सिर्फ 30 दिनों का मिलेगा समय

परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक, जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया जाएगा, जिसके बाद वाहन मालिक को 7 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। इससे पहले वाहनों को छुड़ाने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता था और गाड़ी न छुड़ाने पर 15 दिन को नोटिस जारी करके अंतिम मौका दिया जाता था। साथ ही वाहन मालिक से 200 से 1500 रुपए टोइंग सेवा शुल्क लिया जाता है।हालांकि, यह शुल्क वाहनों की कैटेगरी के हिसाब से लिया जाता है।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बहुत से लोग जब्त सार्वजनिक परिवहन या फिर मालवाहक वाहनों को छुड़ाने नहीं आते हैं, जबकि उनके पास तीन माह का समय होता है। ऐसे में विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए नए नियमों के तहत समय सीमा को घटाया गया है।

सिर्फ 7 दिन का मिलेगा नोटिस

नियमों में बदलाव के बाद भी वाहनों को खींचने के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वाहनों को जब्त करने के बाद अगर 30 दिनों के अंदर नहीं छुड़ाया जाता है, तो वाहन मालिक को 7 दिनों का नोटिस जारी किया जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी जब्त वाहन को नहीं छुड़ाया गया, तो फिर उसे स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा या फिर सार्वजनिक नीलामी कर दी जाएगी।

बता दें कि दिल्ली में अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। परिवहन विभाग के पास उन वाहनों को जब्त करने का अधिकार है, जो सड़क किनारे अवैध पार्किंग में खड़े खड़े किए जाते हैं। ज्यादा वाहन जब्त करने की वजह से पार्किंग में स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है।

मेट्रो से कितनी अलग है नमो भारत ट्रेन? जानें दोनों के बीच 11 बड़े अंतर

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो के बाद एक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं। यह ट्रांसपोर्ट है रेपिड रेल, जिसका ब्रांड नेम ₹नमो भारत₹ है। जानते हैं कि मेट्रो से कितनी अलग है नमो भारत ट्रेन? जानें दोनों में 11 बड़े अंतर।

नई दिल्ली। पहले मेट्रो और अब पहली रेपिड रेल "नमो भारत"। कुछ लोगों का कहना है की दोनो एक जैसी है और कुछ लोगों का कहना है कि दोनों में अंतर है। अगर आप भी कन्फूजन का शिकार हो गए हैं तो यहां जानें की दोनो में आखिर अंतर क्या है ? और नमो इन दोनों से कैसे अलग है।

रैपिड रेल

स्पीड के मामले में रैपिड रेल मेट्रो से कहीं आगे है। इसे एक घंटे में 180 किलोमीटर की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार यात्री केवल एक घंटे में दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। रैपिड रेल के कोच में कई सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, सामान रखने के लिए जगह, और इंफोटेनमेंट सिस्टम। मेट्रो में प्रवेश के लिए स्मार्ट कार्ड, टोकन, क्यूआर कोड वाले पेपर और ऐप से जनरेट होने वाले टिकट का इस्तेमाल किया जाता है जबकि रैपिड रेल में क्यूआर कोड वाले डिजिटल पेपर और पेपर टिकट का इस्तेमाल किया जाता है।

मेट्रो ट्रेन

मेट्रो एक घंटे में 40,000 यात्रियों को यात्रा कराने की क्षमता रखती है। रैपिड रेल और मेट्रो के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी गति में होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली-NCR में चलने वाली मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है जबकि रैपिड रेल को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है।

मेट्रो बनाम नमो भारत

नमो भारत यानि रेपिड रेल परियोजना (Regional Rapid Transit System – RRTS) का पहला दिल्ली-मेरठ रूट शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने इस परियोजना को विकसित किया है। दिल्ली-मेरठ रेपिड रेल रूट पर एक नजर दौड़ाई जाए तो 82.15 किमी इस रूट पर 13 स्टेशन हैं। दिल्ली-गाजियाबाद और मेरठ के इस रूट की दूरी 60 मिनट में पूरी होती है। इसके तहत दिल्ली सेक्शन इस प्रकार हैं।

सराय काले खां (प्रारंभिक स्टेशन)

न्यू अशोक नगर
आनंद विहार
गाजियाबाद सेक्शन
साहिबाबाद

गाजियाबाद
गुलधर
डूंडाहेड़ा
मेरठ सेक्शन
मोदीपुरम (अंतिम स्टेशन)
मेरठ साउथ
मेरठ सेंट्रल
मेरठ नॉर्थ

नमो भारत की खासतौर पर मेट्रो के साथ तुलना की जा रही है पर कुछ विशेषताएं नमो भारत को मेट्रो से काफी अलग बनाती हैं जो इस प्रकार हैं।

मेट्रो के स्टेशनों की दूरी एक किलोमीटर है जबकि नमो भारत के स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग चार किलोमीटर है।

मेट्रो में सामान रखने के लिए रैक नहीं होते जबकि नमो भारत में रैक मिलते हैं।

मेट्रो में हर सीट पर लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्वाइंट नहीं होते लेकिन नमो भारत में ये सुविधाएं मिलती हैं।

मेट्रो में खानपान का सामान नहीं मिलता और खाने का सेवन करना मना भी है जबकि नमो भारत के प्रीमियम कोच में यह सुविधा मिलती है।

मेट्रो में स्ट्रेचर पर मरीज ले जाने की व्यवस्था नहीं है जबकि नमो भारत में यह सुविधा मिलती है।

मेट्रो के स्टेशन दो मंजिल के होते हैं जबकि नमो भारत के स्टेशन दो से चार मंजिल तक के होते हैं।

मेट्रो में प्रीमियम कोच नहीं होता जबकि नमो भारत में प्रीमियम कोच की व्यवस्था है।

मेट्रो पर पुलिस पोस्ट नहीं होते जबकि नमो भारत के हर एक स्टेशन पर पुलिस पोस्ट है।

मेट्रो के दरवाजे अपने आप खुलते हैं जबकि नमो भारत के दरवाजे बटन दबाने पर खुलते हैं।

मेट्रो की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 60 किमी प्रति घंटा होती है जबकि नमो भारत की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है।

मेट्रो के एक कोच में 50 लोग बैठ सकते हैं जबकि नमो भारत के एक कोच में 72 लोग बैठ सकते हैं।

परिवहन विभाग ने दिए निर्देश, बिना सीट बेल्ट-हेलमेट के सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में न हो प्रवेश

यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने यह निर्देश दिए हैं कि बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश न दिया जाए।

सड़क सुरक्षा समिति की हाल में हुई बैठक के बाद प्रदेश में सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सख्ती शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी सीट बेल्ट या हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। इतना ही नहीं सहयात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो।

परिवहन विभाग ने सभी संबंधित को पत्र भेजकर कहा है कि सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्यालयों के गेट पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट व सीट बेल्ट की जांच करें। सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाने वालों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। वाहनों से कार्यालय आने वाले अधिकारी-कर्मचारी इस दौरान मोबाइल का प्रयोग न करें। सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालाध्यक्ष इस निर्देश का सख्ती से पालन करें।

विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, डीएम, पुलिस अधिकारियों को भी इसके अनुपालन के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि यातायात पुलिस व जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करें। कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा है कि यह निर्देश केवल औपचारिकता न होकर, हर अधिकारी व कर्मचारी की सुरक्षा के लिए जरूरत है। हमें इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके लिए दिए गए निर्देश का कड़ी से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इसकी अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भी भेजी जाए।

स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव, कैरियर, रोग और उपाय:

ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश पौराणिक (इंजी)

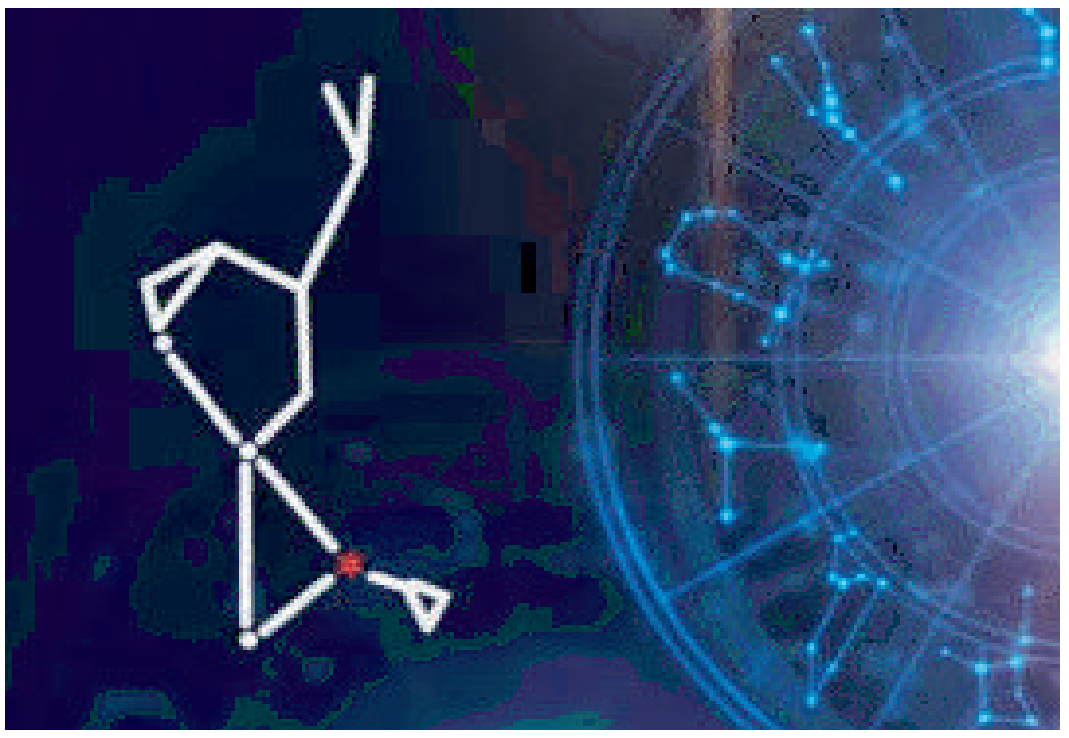

हमारे नक्षत्र मंडल में नारंगी रंग की मणि सरीखा चमकता एक तारा स्वाति नक्षत्र है। स्वाति का अर्थ है शुभ नक्षत्र पुंज। इस नक्षत्र में होने वाली वर्षा को अमृत तुल्य माना जाता है। यदि इस दिन हुई वर्षा के वर्षा के जल को रोगी को दिया जाए तो उसके रोग पीड़ा में कमी आती है। स्वाति नक्षत्र के देवता पवन देव तथा नक्षत्र अधिपति राहु को माना गया है।

स्वभाव: स्वाति नक्षत्र में जन्मा जातक स्वामी भक्त, संकोची, सौम्य प्रकृति का, धैर्यशील, मिलनसार तथा हंसमुख स्वभाव का होता है।

आचार्य वराहमिहिर के अनुसार इस नक्षत्र का जातक शिष्ट, मृदुभाषी, दयावान तथा मातृ पितृ और गुरु भक्त होता है।

कैरियर: इस नक्षत्र में जन्मे जातक कुशल व्यापारी, पायलेट, ड्राइवर,

वकील, न्यायाधीश, खोजी, वैज्ञानिक, संवाददाता, पहलवान, खिलाड़ी,

गुब्बारे तथा पतंग का व्यापार आदि में कैरियर बनाकर सफलता प्राप्त करता है।

रोग: इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को वायु विकार, जोड़ों में दर्द, तनाव,

गैस्ट्रिक, साइटिका आदि रोगों से जूझना पड़ सकता है।

उपाय: स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक को माता सरस्वती की पूजा करना सबसे शुभप्रद माना गया है। प्रतिदिन ॐ ऐं ह्री क्लीं सरस्वत्ये नमः मंत्र का जाप 1 माला करना चाहिए। इसके अलावा सभी कष्टों से मुक्ति हेतु हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभकारी होता है।

सफेद तथा नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग इन्हे शुभप्रद होता है।

AI-पावर्ड 'डेथ क्लॉक' आप कब मरेंगे इसकी भविष्यवाणी करता है, जाने पूरी जानकारी

जबसे एआई आया तबसे तकनीकी क्षेत्र में बदलाव हुआ है। इस समय AI पावर्ड 'Death Clock' काफी ट्रेंड में है। बता दें कि, यह वेबसाइट यूजर को उनकी डेथ डेट दावा करती है। यह एकदम फ्री है, जो सिर्फ एज, बॉडी मास इंडेक्स, डाइट, एक्सरसाइज लेवल्स और स्मोकिंग हैबिट्स जैसे डेटा को विशलेषण करके मौत की तारीख बताता है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।

किसी व्यक्ति की मृत्यु कब हो सकती है। इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता है। लेकिन क्या आप ने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, 'मैं कब मर सकता हूं', तो यह नया एआई डेथ क्लॉक ट्रेंड निश्चित रूप से आपको इससे जोड़े रखेगा। बता दें कि, एआई-संचालित 'डेथ क्लॉक' आपके डेट ऑफ बर्थ, फिटनेस रुटीन, धूम्रपान या शराब की आदतों सहित विभिन्न संकेतों का उपयोग करके और आपके लिए मृत्यु की तारीख की भविष्यवाणी करता है और विशलेषण करके आपकी मृत्यु के स्पष्ट समय की गणना करता है। डेथ क्लॉक नामक निःशुल्क वेबसाइट आपके निधन की तारीख के साथ-साथ आपकी मृत्यु कैसे होगी बताता है।

न्यू एआई डेथ क्लॉक वायरल ट्रेंड बन गई है

पीपल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 63 मिलियन से ज्यादा लोग इस साइट पर आ चुके हैं और इस क्लॉक का इस्तेमाल डेथ की तारीख और समय को समझने के लिए कर चुके हैं, जिस दिन वे 'मरने' वाले हैं। रिपोर्टों के अनुसार, यह मृत्यु घड़ी घंटों, मिनटों और सेकंडों तक आपकी मृत्यु की तारीख की भविष्यवाणी करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स, जन्म तिथि, शराब और धूम्रपान के सेवन, फिटनेस, आहार और देश सहित विभिन्न संकेतों का उपयोग करने का दावा करती है। चाहे यह कितना भी डरावना क्यों न लगे, हालांकि नेटिजन्स इस बारे में बातें कर रहे हैं..

एआई डेथ क्लॉक से लाइफटाइम कैसे बढ़ा सकते हैं

बता दें कि, यह साइट मृत्यु की तारीख और समय के साथ यूजर्स की मृत्य का कारण भी बताती है। इसके साथ ही वेबसाइट पर एक डिस्केलमर भी दिया गया है, जिसमे लिखा है कि डेथ क्लॉक का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह कैलकुलेटर आपकी असल डेट ऑफ डेथ की भविष्यवाणी नहीं करता है। यह संभावना नहीं है कि यह मृत्यु की तारीख का सटीक अनुमान लगा सके। यदि आप 'लंबे समय तक जीवित रहना' चाहते हैं, तो शराब और धूम्रपान की आदतों को कम से कम रखना इस प्रयोग के लिए उपयोगी होगा, जिससे आपका जीवनकाल बढ़ जाएगा।

महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे प्रयागराज तो इन जगहों को भी करें एक्सप्लोर, बच्चे भी हो जाएंगे खुश

अगर आप भी प्रयागराज संगम स्नान के लिए जा रहे हैं, तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको प्रयागराज में स्थित कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

हिंदू धर्म में महाकुंभ मेला एक खास जगह रखता है। यही वजह है कि यहां पर स्नान करने के लिए अब तक करोड़ों लोग जा चुके हैं। आस्था, भक्ति और परंपरा के इस संगम में बच्चों से लेकर बुजुर्ग और युवा तक हर कोई जा रहा है। इस मेले की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार साल 2025 में यह मौका आया है। इस महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।

माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, तो व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी प्रयागराज संगम स्नान के लिए जा रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको प्रयागराज में स्थित कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद पार्क

संगम स्नान के बाद अगर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो आप अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद पार्क में आ सकते हैं। यह पार्क हरा-भरा है और भीड़भाड़ से दूर ले जाता है। बच्चों को भी यहां आकर अच्छा लगेगा और आपको भी बच्चों पर नजर रखने की जरूरत नहीं होगी। यह एक बेहद खूबसूरत जगह है। जहां पर आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। यहां पर एंट्री टिकट 5 रुपए है और पार्क में रहने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। साथ ही आपको यहां पर पानी और वॉशरूम आदि की सुविधा भी मिल जाएगी।

खुसरो बाग, प्रयागराज

इसके अलावा आप बच्चों के साथ खुसरो बाद भी जा सकते हैं। यह प्रयागराज का एक विशाल ऐतिहासिक बाग है और इस पुराने स्मारक का अच्छे तरीके से रखरखाव किया गया है। इसलिए आपको यहां विजिट करके अच्छा लगेगा। हालांकि यह जगह थोड़ा भीड़भाड़ वाली हो सकती है। यहां जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के पास वाले गेट से एंट्री लेनी होगी। इससे आपको रेलवे स्टेशन आने में परेशानी नहीं होगी। दरअसल, महाकुंभ तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसलिए आपको प्रयागराज आने में मुश्किल नहीं होगी। वहीं अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी सही स्थान पर पार्क करें। क्योंकि अगर आप गेट के किनारे या फिर रोड पर कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, तो आपकी गाड़ी तो उठा लिया जाएगा।

मां ललिता देवी मंदिर

अगर आप श्रीमां ललिता देवी मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो आपको 12 बजे से पहले या फिर शाम को 04:30 बजे के बाद मंदिर जाएं। क्योंकि इसके बीच मंदिर बंद रहता है। यह स्थान बेहद स्वच्छ और शांतिपूर्ण है। यहां पर मंत्र की ध्वनि और हवन की खुशबू आपको सुकून का एहसास करवाएगी। यह एक शक्तिपीठ मंदिर है, जोकि मीरापुर प्रयागराज में स्थित है।

आइब्रो बनवाते समय क्या आपके भी होती है जलन, इन 3 अचूक उपाय को करें, पार्लर जाने से नहीं लगेगा डर

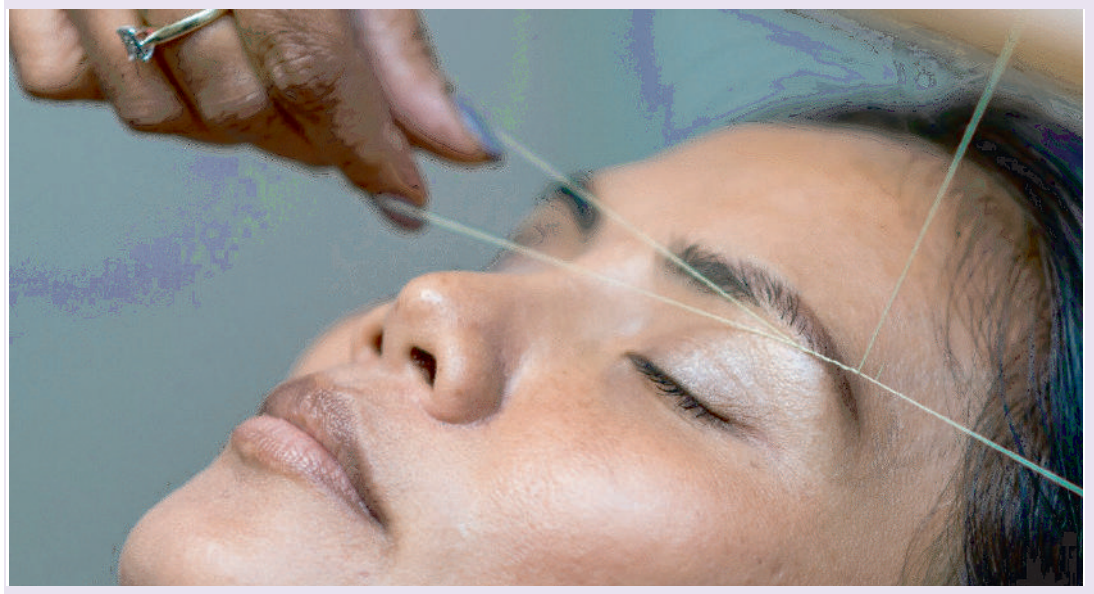

कई बार महिलाएं पार्लर जाती हैं, तो उन्हें आईब्रों बनवाते समय काफी समस्या झेलनी पड़ती है। अब आईब्रो बनवाते समय असहनीय जलन झेलना नहीं पड़ेगा, आप इन घरेलू उपाय से अपनी प्रॉब्लम को दूर करके राहत पहुंचा सकते हैं।

महिलाएं जब भी पार्लर आईब्रो बनवाने जाती है, तो उन्हें त्वचा पर दाने निकलने, रेडनेस, जलन और दर्द की शिकायत रहती है। वैसे तो वैक्सिंग या थ्रेडिंग के दौरान त्वचा को महसूस होने वाले खिंचाव की वजह से होता है। आईब्रो बनवाने के बाद इसका असर कई घंटो तक महिलाओं के चेहरे पर बना रहता है। इस समस्या बचने के लिए आप जरुर कोई दवा या उपाय जरुर खोजती होगी। यदि आपको भी इस तरह की परेशानी होती है, तो आप इन घरेलू उपाय के जरिए अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं।

थ्रेडिंग के बाद आप दर्द और जलन से छुटकारा के लिए ये उपाय

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल में शीतलता के गुण पाएं जाते हैं। यह त्वचा को ठंडक पहुंचाकर सूजन, जलन और लालिमा को कम करने में मदद करता है। एलोवेरा के इस उपाय के करने से त्वचा की जलन दूर हो जाती है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल को त्वचा पर लगाकर थोड़ी देर मसाज करें। बाद में चेहरे को धो लें।

खीरे का रस

आईब्रो बनवाते समय कई बार स्क्रैच आ जाते है और त्वचा की जलन को भी दूर करता है। खीरे का रस त्वचा को ठंडक और राहत देता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जलन को कम करने में मदद करता है। आप खीरे के टुकड़े को प्रभावित जगहों पर रगड़ सकते हैं। इसे आप 15 मिनट तक लगा रहने दें इसके बाद चेहरे को धो सकते हैं।

गुलाब जल

त्वचा को शांत करने के लिए गुलाब जल भी काफी फायदेमंद होता है। गुलाब जल के इस उपाय को करने के लिए कॉटन में गुलाब जल लेकर प्रभावित क्षेत्र पर लगा सकते हैं। कुछ देर के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हैं।

अब नहीं करनी पड़ेगी कई सरकारी ऐप्स की झंझट, भारत सरकार लाएगी सुपर ऐप

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। अभी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, उमंग, डिजिलॉकर, भीम यूपीआई, आरोग्य सेतु, और आधार आदि।

भारत सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नागरिकों के लिए एक नई पहल करने जा रही है। वर्तमान में सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, जिससे उन्हें असुविधा होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक ₹Government App Suit₹ लाने की तैयारी कर रही है, जहां सभी सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे नागरिकों को सुविधाजनक और सुगम डिजिटल सेवाएं मिल सकेंगी।

सरकार का ऐप सुइट: क्या है योजना ?

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। अभी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, उमंग, डिजिलॉकर, भीम यूपीआई, आरोग्य सेतु, और आधार आदि। इन सभी को उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग डाउनलोड और अपडेट करना पड़ता है।

इस नए ऐप सुइट के माध्यम से नागरिकों को सभी महत्वपूर्ण सरकारी ऐप्स एक ही स्थान पर मिलेंगे, जिससे न केवल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, बल्कि उपयोगकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी सीधे मिल सकेगी। यह ऐप सुइट एक ₹सुपर ऐप₹ की तरह कार्य करेगा, जिसमें नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक त्वरित और आसान एक्सेस मिलेगा।

स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल

सरकार इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टेक कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने गूगल और ऐपल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे अपने ऐप स्टोर्स पर इस सरकारी ऐप सुइट को डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं से भी अनुरोध किया है कि वे इस ऐप सुइट को प्री-इंस्टॉल करके फोन में पहले से ही उपलब्ध कराएं। ऐसा करने से नागरिकों को अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, और वे फोन खरीदते ही सभी आवश्यक सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

ऐप सुइट से मिलने वाले फायदे

सरकारी ऐप सुइट के आने से आम नागरिकों को कई फायदे होंगे, जैसे:

1. एक ही जगह पर सभी सरकारी सेवाएं: नागरिकों को अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

2. सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी: सभी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी ऐप सुइट के माध्यम से उपलब्ध होगी।

3. डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच: लोगों को सरकारी सेवाओं तक त्वरित और आसान एक्सेस मिलेगा।

4. डेटा सुरक्षा और विश्वसनीयता: चूंकि यह ऐप सुइट सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा, इसलिए इसका डेटा सुरक्षित और विश्वसनीय रहेगा।

5. कम स्टोरेज की खपत: एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी ऐप्स होने से मोबाइल स्टोरेज की बचत होगी।

भारत सरकार का यह नया ऐप सुइट नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुगम, तेज और सुरक्षित बनाएगा। हालांकि, गूगल और ऐपल जैसी टेक कंपनियों के विरोध से इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। यदि यह ऐप सुइट सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को और अधिक सशक्त करेगा और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का उपयोग पहले से कहीं अधिक आसान बना देगा।

इस पहल को लेकर गूगल और ऐपल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। गूगल ने इस योजना का विरोध किया है, जबकि ऐपल भी इसे लेकर सकारात्मक रुख नहीं अपना रहा है। टेक कंपनियों का मानना है कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ऐप्स से उन्हें न केवल कंट्रोल मिलता है, बल्कि एक बड़ा रेवेन्यू भी आता है। यदि सरकार अपने ऐप सुइट को स्टोर्स पर उपलब्ध कराती है या इसे स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो इससे गूगल और ऐपल के रेवेन्यू मॉडल और कंट्रोल पर असर पड़ सकता है। गूगल और ऐपल की असहमति को देखते हुए भारत सरकार इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपना सकती है। सरकार का मानना है कि डिजिटल सेवाओं को सभी नागरिकों तक पहुंचाना उसका मुख्य उद्देश्य है, और किसी भी निजी कंपनी को इस रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। इसलिए, यदि गूगल और ऐपल इस पहल में सहयोग नहीं करते, तो सरकार अन्य उपायों पर विचार कर सकती है, जैसे कि स्वदेशी ऐप स्टोर का निर्माण या नए नियमों के तहत गूगल और ऐपल को सरकारी ऐप्स को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना।

कच्चा प्याज खाने से शरीर को घेर सकती हैं गंभीर बीमारियां, एक्सपर्ट से जानिए इसके घातक नुकसान

प्याज भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रहा है। अगर आप रोजाना कच्चे प्याज का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपको शरीर पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं।

प्याज भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रहा है। फिर चाहे दाल बनाना हो या सब्जी बनानी हो या फिर स्पेशल डिश, अधिकतर घरों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लोग सलाद के रूप में भी प्याज खाते हैं। बता दें कि प्याज में सोडियम, फोलेट, पोटैशियम, विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है। इसके अलावा प्याज में मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जोकि शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना कच्चे प्याज का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपको शरीर पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे है कि कच्चे प्याज का अधिक सेवन करने से इसके क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।

पेट से जुड़ी परेशानियां

दरअसल, कच्चे प्याज का अधिक सेवन करने से आपको पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। खासतौर पर अगर आपको पहले से पेट संबंधी कोई समस्या है, तो आपको सीमित मात्रा में प्याज का सेवन करना चाहिए। क्योंकि प्याज में 'फ्रुक्टेन' नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जिसकी वजह से इसको पचाने में परेशानी हो सकती है। कच्चे प्या का अधिक सेवन करने से कब्ज, एसिडिटी, गैस और अपच जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जिन लोगों का पेट सेंसिटिव है, तो आपको सूजन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

बढ़ सकता है माइग्रेन का दर्द

अगर आको माइग्रेन की समस्या है तो आपको सीमित मात्रा में ही कच्चे प्याज का सेवन करना चाहिए। बता दें कि प्याज में टायरामाइन पाया जाता है, जो सिरदर्द की समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर आपको अक्सर सिरदर्द या फिर माइग्रेन की समस्या रहती है, तो आपको कच्चे प्याज का सेवन कम करना चाहिए। वहीं रात के समय प्याज खाने से बचना चाहिए।

सीने में जलन की समस्या

अधिक मात्रा में कच्चे प्याज का सेवन करने से सीने में जलन या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। प्याज में भरपूर मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जब पोटैशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यह आपके कार्डियोलीवर को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपके सीने में जलन हो सकती है। वहीं ज्यादा मात्रा में प्याज खाने से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। अगर आपको पहले से इन दोनों में से कोई समस्या है तो आपको सीमित मात्रा में प्याज का सेवन करना चाहिए।

लो हो सकता है शुगर लेवल

बता दें कि शुगल लेवल बढ़ने के अलावा शुगर लेवल लो होना भी खतरनाक होता है। इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। वहीं कच्चे प्याज का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से कम हो सकता है। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, उनको डॉक्टर की सलाह पर ही कच्चे प्याज का सेवन करना चाहिए।

हम लोग देश और साफ-सुथरी राजनीति के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं- मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से पार्टी की भविष्य की रणनीतियों की जानकारी साझा की और उनके सुझाव भी लिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक तरफ़ हमारा लक्ष्य है सरकार बनाकर व्यवस्था ठीक करना लेकिन हम सिर्फ़ सत्ता के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बदलाव के लिए आए हैं और हमें खुशी है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को भी आज शिक्षा - स्वास्थ्य पर बात करनी पड़ रही है। यह बदलाव की शुरुआत है। हमारी लड़ाई सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों की सोच और उनकी प्राथमिकताओं को बदलना भी हमारे आंदोलन का हिस्सा है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत जनहित के अन्य क्षेत्रों में बदलाव करके दिखाया है। अगर भाजपा की सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो यह भी हमारी जीत होगी, क्योंकि हम खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत जरूरी मुद्दों पर परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अगर दूसरी पार्टियां अपनी परंपरागत राजनीति, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जाति व धर्म की लड़ाइयां छोड़ कर इस दिशा में बात भी करने लगती हैं, तो इसे भी हमें अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। हालांकि अभी इनके लिए इस पर काम करना बहुत दूर की बात है।

मनीष सिसोदिया ने देशभर के ₹आप₹ सोशल मीडिया टीम के साथ ऑनलाइन बात करते हुए कहा कि भले ही चुनाव के नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आए, लेकिन सबने खूब मेहनत की है। कई वॉलंटियर्स दिल्ली की गलियों में उतरे हुए थे। हम सब मिलकर एक चुनाव नहीं, बल्कि एक आंदोलन के लिए लड़ रहे थे। हम अपने उस सपने को जी रहे थे कि राजनीति ईमानदारी और काम की भी हो सकती है। जब इस देश की राजनीति जाति, धर्म और गुंडागर्दी से घिरी हुई है, ऐसे में कोई एक पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी के दम पर चुनाव लड़ सकती है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी लड़ाई केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई केवल इसलिए नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए, बल्कि हमारी लड़ाई इसलिए है कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। हर

गरीब को अमीर होने का हक मिले। देश की राजनीति गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, धर्म और जाति के ठेकेदारों से मुक्त हो और एक व्यक्ति के विकास के लिए जो मुद्दे जरूरी हैं, उसकी राजनीति हो। हमने चुनाव में केवल वोट नहीं मांगे थे, बल्कि बदलाव की नींव रखी थी। इस नींव को हमने सफलतापूर्वक रखा है। इस बदलाव की नींव रखने में हम कामयाब हुए हैं।

उन्होंने वॉलंटियर्स से कहा कि आप सब इसे सत्ता के लिए लड़े गए चुनाव के रूप में देखने के बजाय एक विचार की लड़ाई के रूप में देखिए। विचार की लड़ाई में, विचार कभी नहीं हारता। वह और मजबूत होकर उठता है। जब विचार बार-बार मजबूत होकर उठता है, तभी इतिहास बनता है। आज हमारी लड़ाई एक मोड़ पर आ गई है।

सिसोदिया ने कहा कि जब हमने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति शुरू की थी, तो किसी ने सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं। लोग मजाक उड़ाते थे कि अब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देंगे! उन लोगों ने मजाक बनाया और हमने करके दिखा दिया। मोहल्ला क्लीनिक बनाने को लेकर कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल का मजाक बनाया था। लेकिन हमने देखा कि उनका मजाक उन पर ही भारी पड़ा और आज मोहल्ला क्लीनिक ऐसा मॉडल है जिसे पूरी दुनिया और देश के कई राज्य फॉलो कर रहे हैं। जब हमने बिजली-पानी फ्री किया, तब भी ये लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी भी आम आदमी पार्टी के मॉडल को फॉलो कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम एक चुनाव में हार से उदास हो जाएं, ऐसे कमजोर लोग नहीं हैं। किसी की मेहनत बेकार नहीं गई। हम देश के भविष्य के लिए काम कर रहे थे। भले ही एक चुनाव में मन मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई आगे बढ़ी है। इसको और आगे बढ़ाएंगे और अगले चुनाव में और शिद्दत से लड़ेंगे। अभी तो मैं दिल्ली में शिक्षा पर काम कर रहा था, लेकिन अब मैं देशभर में शिक्षा पर काम करने के लिए समय निकाल पाऊंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें नई ऊर्जा के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखना है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम जिस विचार के लिए लड़ने के लिए आए थे, वह लड़ाई जारी है।

सिसोदिया ने कहा कि इस बार दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खुलेआम पैसे, साड़ी और शॉल बांटे जा रहे थे लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि उसे कुछ नहीं दिखा। पुलिस उनका साथ दे रही थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए लेकिन नतीजे जो भी हैं आज सबके सामने हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगले चुनाव में यह सारी गड़बड़ियां न हों। इससे सीख लेते हुए कि अगले चुनाव में ये लोग फिर ऐसी गड़बड़ियां न कर सकतें उसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर हमारे पास कई आइडिया हैं। दिल्ली में हमारी सरकार को जितना समय मिला उसमें हमने कई काम किए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और वेलफेयर की जो बुनियाद रखी अगर आने वाली भाजपा सरकार उसे आगे बढ़ाएगी तो हमें खुशी होगी कि हमने काम की राजनीति की जो बुनियाद रखी उसे बाकी पार्टियां भी आगे बढ़ाने के लिए मजबूर है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। देश की और पार्टियों को भी हम शिक्षा पर काम करने के लिए जोर देंगे।

महाकुंभ में सनातन धर्म, संस्कृति एवं आस्था का अद्भुत संगमः इटेला राजेंद्र

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। सनातन धर्म अनुरागी पेरिका सुरेश पिछले 27 दिनों से प्रयागराज महाकुंभ में लगातार भक्तों एवं जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं।उन्होंने अपने इस पुण्य कार्य से न सिर्फ भक्त जनों का बल्कि साधु संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया है।श्री सुरेश ने बताया कि इटेला राजेंद्र जो मल्काजगीरी तेलंगाना से भाजपा सांसद हैं उन्होंने माघ पूर्णिमा के अवसर पर अपने साथ 45 श्रद्धालुओं को लाकर प्रयागराज संगम में अमृत एवं शाही स्नान कराया।श्री राजेंद्र तेलंगाना के पहले वित्त मंत्री तथा बाद में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी में उनका कद काफी बड़ा है। इसको देखते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व उन्हें तेलंगाना प्रदेश की कमान सौप सकती है। सांसद राजेंद्र के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती डी के अरुणा, पूर्व सांसद बीबी पाटील, वेणुगोपाल रेड्डी, गिरिवर्धन रेड्डी, मुरली मधुसूदन राव, डी नंदकिशोर, बी महिपाल रेड्डी, आदि ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान किया। सनातन धर्म प्रचारक पेरिका सुरेश 27 दिनों से संगम पर उपस्थित भक्त समूह की भरपूर सेवा कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो इसकी व्यवस्था में लगे हुए इसके अलावा प्रतिदिन 2000 भक्त जनों को भोजन एवं 10,000 साधु संतों को उन्होंने कंबल वितरित किया। यह उनके सनातन धर्म के प्रति आस्था विश्वास एवं धर्म के निस्वार्थ सेवा की भावना को प्रदर्शित करता है।

दिल्ली में पूर्वांचली को CM बनाकर इस राज्य पर फोकस का है प्लान? एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में BJP

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद सीएम पद के लिए नाम के ऐलान को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी पूर्वांचल के किसी नेता को दिल्ली की गद्दी सौंप सकती है। इस सवाल को जवाब में बदलने के कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद सीएम पद के लिए नाम के ऐलान को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं, राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी पूर्वांचल के किसी नेता को दिल्ली की गद्दी सौंप सकती है। इस सवाल को जवाब में बदलने के कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं।

बिहार के किसी नेता को मिलेगी गद्दी!

खास बात यह है कि पूर्वांचल के नेताओं में से बिहार से ताल्लुक रखने वाले किसी नेता को बीजेपी दिल्ली की गद्दी सौंप सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसा करके बीजेपी न सिर्फ दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों को खुश कर सकती है, बल्कि एक हजार किलोमीटर दूर रहने वाले बिहारियों का दिल भी जीतने की कोशिश कर रही है। हालांकि, ऐसा करके बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध सकती है।

बिहारियों का दिल्ली से गहरा नाता

बता दें कि पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली से बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। चाहे रोजगार हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा, बिहार और पूर्वी यूपी का शायद ही कोई घर हो जिसके लोग इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली न आते हों। अगर बीजेपी पूर्वांचल के किसी नेता को दिल्ली का सीएम बनाती है तो इसका न सिर्फ सकारात्मक असर होगा बल्कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा।

सत्ता में लाने में पूर्वांचली मतदाताओं का हाथ

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की कुल 18 विधानसभा सीटों में से 10 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जिनमें झुग्गी बस्तियों की बहुलता है। 10 सीटें ऐसी हैं, जिन पर झुग्गी बस्तियों के मतदाता जीत-हार का फैसला करते हैं। इनमें से 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इन 28 सीटों में पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

इससे साबित होता है कि पूर्वांचल के मतदाताओं ने हमेशा की तरह भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। यह बड़ी बात है कि पूर्वांचल के लोगों ने भाजपा को कुल 17 सीटें जीतने में मदद की है। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों भाजपा पर भरोसा जताने के बदले उन्हें तोहफा देकर पार्टी

अगले चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय कर सकती है।

बने सीएम तो इनके नाम लगेगी मुहर

अब सवाल यह उठता है कि अगर बीजेपी पूर्वांचल से सीएम बनाती है तो किन नामों पर दांव पर लग सकता है, तो बता दें कि दिल्ली बीजेपी में पूर्वांचल यानी खासकर बिहार से कई नेता हैं जो इस साल चुनाव जीतकर आए हैं। अगर ऐसा होता है तो अभय वर्मा, डॉ पंकज कुमार सिंह और चंदन कुमार चौधरी का नाम फाइनल हो सकता है।

हालांकि, दरभंगा के रहने वाले अभय वर्मा को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वह दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और पेशे से वकील हैं। दूसरे दावेदार हैं खगड़िया के रहने वाले चंदन चौधरी, जिन्होंने दिल्ली की संगम विहार सीट जीती है।

तीसरे दावेदार की बात करें तो मूल रूप से बक्सर के रहने वाले डॉ. पंकज कुमार सिंह ने विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलाया है।

दिल्ली में इस सप्ताह 30 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, वसंत नहीं अब सीधे सर्दी के बाद गर्मी का होगा एहसास?

दिल्ली में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फरवरी के पहले पखवाड़े में ही तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है और जल्द ही यह 14 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार फरवरी में देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह ही दिल्ली में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है।

दिल्ली। इसे जलवायु परिवर्तन का असर कहें या फिर साल दर साल बदल रही मौसमी परिस्थितियां...सर्दियों के बाद गर्मी से पूर्व अब संधिकाल सरीखा एहसास नहीं होता। वसंत आता है, लेकिन गुलाबी ठंड महसूस नहीं होती। इस साल तो आलम यह है कि फरवरी के पूर्वार्द्ध में ही तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है।

सुबह- शाम कहने भर को ठंड है जबकि दिन में धूप पसीना निकालने लगी है। फरवरी में अभी उत्तरार्ध पूरा बचा है तो होली भी अभी दूर है। ऐसे में रिकार्डतोड़ गर्मी पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

तीन दिन से लगातार बढ़ रहा तापमान

पिछले तीन दिन से दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ रहा है। नौ फरवरी को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री रहा तो दस फरवरी को 28 डिग्री पहुंच गया। 11 तारीख को 29.7 डिग्री पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखी जा रही है। जल्द ही यह 14 डिग्री तक पहुंच जाएगा।

मशहूर है दिल्ली की सर्दी

दिल्ली की सर्दियों को आमतौर पर सितम ढाने वाली माना जाता है। जबकि इस बार पूरा जनवरी माह बीत गया लेकिन कम ही दिन रहे जब लोगों को कड़ाके की सर्दियों का एहसास हुआ। पूरे जनवरी महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब शीत लहर या शीत दिवस की स्थिति बनी हो। इसकी तुलना अगर पिछले साल से करें तो वर्ष 2024 के जनवरी महीने में पांच दिन ऐसे रहे थे जब शीतलहर की चली थी और लोगों को ठिठुरन भरी सर्दी झेलनी पड़ी थी। कमोबेश ऐसी ही स्थिति इस साल फरवरी में बनी हुई है।

जनवरी रही थी आठ सालों में सबसे गर्म

कमजोर पश्चिमी विक्षोभों से राजधानी में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। जनवरी में भी रातें नौ साल और दिन बीते छह सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहे। चिंता की बात यह कि फरवरी में देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह ही दिल्ली में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है।

जनवरी में 65 तो फरवरी में 94 प्रतिशत कम वर्षा

दिल्ली में जनवरी के बाद फरवरी का महीना भी सूखा ही बती रहा है। जनवरी में औसतन 19.2 मिमी वर्षा होती है। लेकिन इस बार सिर्फ 6.6 मिमी हुई है यानी 65 प्रतिशत कम। इसी तरह फरवरी में 12 तारीख तक सामान्य वर्षा 8.6 मिमी है जबकि हुई है 0.5 मिमी यानी 94 प्रतिशत कम।

कम वर्षा के चलते बादल भी कम रहे हैं और हवा में नमी भी कम बनी। बादल नहीं रहने से धूप तेज रही और नमी कम होने के चलते कोहरा भी कम रहा। यही वजह है कि जनवरी के बाद अब फरवरी भी गर्म होता जा रहा है।

इन पांच कारकों से ज्यादा गर्म रहा मौसम

मौसम को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहे। इनकी संख्या तो सामान्य रही लेकिन प्रभाव कम रहा।

कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर भारी बर्फबारी वाले दिनों की संख्या आमतौर पर कम रही।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते चक्रवाती हवा का क्षेत्र आमतौर

पर बनता है, लेकिन कमजोर विक्षोभ के चलते ऐसा नहीं हुआ।

मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र नहीं बनने के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश भी सामान्य से कम हुई।

बारिश कम होने के चलते मौसम में नमी कम रही, इसके चलते कोहरे वाले दिन और कोहरे के समय में भी कमी आई।

दिल्ली में अगले 100 दिन क्या-क्या काम करेगी नई सरकार? रोडमैप तैयार करने में जुटे अधिकारी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में अगले सप्ताह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के साथ अधिकारी 'विकसित दिल्ली' और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की तैयारी में जुटे हैं।

इसके अलावा सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से निपटने के लिए योजना तैयार करने में भी व्यस्त हैं।सरकार की सभी प्राथमिकताएं लागू करने के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने हाल ही में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में उन्हें बृहस्पतिवार तक अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

15 दिन, मासिक और 100 दिनों की होगी कार्ययोजना

मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार कार्ययोजना में 15 दिन, मासिक और 100 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सभी विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार करना शुरू करें, जिन्हें नई भाजपा सरकार पदभार ग्रहण करने के बाद पहले शुरू कर सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) 100 दिनों के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखेगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत

स्वास्थ्य बीमा योजना (Ayushman Bharat Yojana) को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था।

आयुष्मान भारत योजना को पिछली सरकार ने नहीं किया था लागू

विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सभी शीर्ष भाजपा नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है, साथ ही राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त कवर भी दिया जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि विभाग प्रमुखों को केंद्र सरकार की अन्य कई योजनाओं पर काम शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है, जिन्हें पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग आदि बरसात के मौसम में जलभराव को रोकने के लिए नालों की उचित सफाई और सफाई के लिए कदम उठाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो की रिपोर्ट की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

CM की घोषणा के बाद ही सरकार के कार्यभार संभालने की उम्मीद

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के साथ शहर के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें नागरिक मुद्दों से संबंधित त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के साथ वास्तविक समय के आंकड़ों को साझा करने के उद्देश्य से इसकी सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की गई।

सभी विभागों को विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत की गई गैर-सरकारी नियुक्तियों की सूची प्रस्तुत करने और बृहस्पतिवार तक सेवा विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि अधिकारी नई सरकार और मंत्रियों के समक्ष संगठनात्मक संरचना और संबंधित विभागों और एजेंसियों में निभाई गई भूमिका सहित पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। पार्टी द्वारा नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के बाद अगले सप्ताह सरकार के कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

भाजपा अभी तक दिल्ली को नहीं दे पाई मुख्यमंत्री, लगने लगे लंबे-लंबे पावर कट - आप

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के अंदर चल रही आपसी लड़ाई का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगताना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आए कई दिन हो गए हैं लेकिन भाजपा अभी तक दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है और लंबे-लंबे पावर कट लगते शुरू हो गए है। भाजपा की आपसी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? इसलिए भाजपा को अपनी लड़ाई बंद करके दिल्लीवालों को उनका मुख्यमंत्री देना चाहिए और दिल्ली के गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए।

प्रियंका कक्कड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं होना भाजपा में गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में इनके गुट मिल रहे हैं, क्योंकि ये

लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, मगर इस लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों से लंबे-लंबे पावर कट लगने की खबरें आई हैं। भाजपा को अपनी आपसी लड़ाई बंद करके जल्दी से अपना सीएम नियुक्त करना चाहिए और दिल्ली के गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमारे यहां लगातार बैठकें हो रही हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से अरविंद केजरीवाल संगठन, पंजाब के नेता, जीते हुए विधायकों और जो नहीं जीत पाए उन उम्मीदवारों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। जो भी चीज ठीक करने की जरूरत होगी, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में लंबे-लंबे पावर कट लग रहे हैं, क्योंकि भाजपा अभी तक दिल्लीवालों को एक सीएम नहीं दे पाई। भाजपा को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। इस पर जल्द काम होना चाहिए।

निकाय चुनाव को लेकर बढ़ेगी सरगर्मी, प्रचार में उतरेंगे राज बब्बर समेत 20 नेता

गुरुग्राम निकाय चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने प्रचार समिति सहित कई कमेटियों का गठन किया है। राज बब्बर कैप्टन अजय यादव सुखबीर कटारिया समेत 20 से ज्यादा प्रदेश स्तरीय नेता जिले में होने वाले निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे। पार्टी हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा। गुड़गांव सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता राज बब्बर, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, सुखबीर कटारिया, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज समेत 20 से ज्यादा प्रदेश स्तरीय नेता जिले में होने वाले निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे।

हरियाणा में कांग्रेस ने निकाय चुनावों को लेकर गुरुग्राम जिले की कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है।

लोकसभा चुनाव में गुड़गांव सीट पर कैसा था कांग्रेस का प्रदर्शन?

ऐसे वरिष्ठ नेताओं को जिले में प्रचार की कमान सौंपी जा रही है, जो जनता को साध सकते हैं। राज बब्बर 2024 का लोकसभा चुनाव गुड़गांव सीट से लड़ चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बल्कि पिछले दो बार हुए लोकसभा चुनावों से ज्यादा वोट भी लिए थे।

लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन और बढ़े वोट बैंक ने ही जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा को भरने का काम किया। वहीं इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी सभी प्रत्याशियों और पूर्व मंत्रियों ने बेहतर काम किया। इसलिए इन सभी वरिष्ठ नेताओं को भी प्रचार कमेटी में जगह दी गई। ये सभी नेता अपने-अपने क्षेत्र में जनता को अपनी संवाद कला से साध सकते हैं।

प्रचार में उतरेंगे ये नेता

गुरुग्राम जिला कांग्रेस के सह प्रभारी अशोक बुवानीवाला के मुताबिक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे व राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य वर्धन यादव, मोहित ग्रोवर, रोहताश खटाना, पर्ल चौधरी के अलावा वरिष्ठ नेता पंकज डावर, कमलबीर यादव, विरेंद्र यादव, रोहताश बेदी, सुनीता वर्मा प्रचार करेंगे।

मैनिफेस्टो कमेटी किसे किया गया शामिल?

इसके अलवा आशीष दुआ, सुनीता सहरावत, शमसुद्दीन, साहिदा खान, केएल यादव, विपिन खन्ना, ओमप्रकाश पांचाल, कुलराज कटारिया, गजेंद्र

चौहान, लाल सिंह यादव, निर्मल यादव, पूजा शर्मा, रमेश शर्मा, प्रवीन सरपंच, सीमा हुड्डा, एडवोकेट संतोख सिंह, मुकेश शर्मा व महाराज सिंह भी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मैनिफेस्टो कमेटी में भी इन नेताओं को शामिल किया गया है।

वहीं टिकट को लेकर बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी में पूर्व मंत्री व गुरुग्राम जिला प्रभारी करण सिंह दलाल, पंकज डावर, अशोक गर्ग बुवानीवाला, राजाराम, विरेंद्र यादव, सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया कमेटी में पंकज डावर, निशित कटारिया, अमित यादव, पंकज भारद्वाज, मनीष खटाना को शामिल किया गया है।

इन कमेटियों में यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई प्रेसिडेंट भी सदस्य होंगे। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ रही है। गुरुग्राम नगर निगम व मानेसर नगर निगम के चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारकर पार्टी अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेगी।

पांच कॉलोनियों पर जमकर गरजा बुलडोजर, 95 बीघा जमीन पर हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद के मटियाला गांव निकट फ्रेंडस कॉलोनी में करीब 95 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही पांच अवैध कॉलोनियों को जीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।

वहीं, कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम का कालोनाइजर ने अपने लोगों के साथ विरोध किया, जिस पर पुलिस बल ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया।

जीडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से चारदीवारी तोड़ी

बताया गया कि मंगलवार को जीडीए की प्रवर्तन जोन-3 की टीम ने मटियाला गांव के निकट अशोक जैन और सचिन चौधरी 25 बीघा भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रहे थे। सूचना पाकर जीडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से चारदीवारी तोड़ दी।

अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया

जीडीए की टीम के अनुसार, कॉलोनी परिसर में किए गए निर्माण को भी ध्वस्त करते हुए बनाई गई कुछ सड़कों को उखाड़ा गया। इसके बाद टीम ने गोविंद धाम कॉलोनी पहुंच कर 22 बीघा जमीन में नीरज मलिक और योगेश चौधरी द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।

टीम ने मटियाला गांव में 16 बीघा और 20 बीघा क्षेत्र में मुकेश वर्मा द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के भूखंडों में चारदीवारी, सड़क, विद्युत पोल आदि ध्वस्त किए।

अवैध कालोनी बनाने वाले तीन लोगों पर मुकदमा

जीडीए ने बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने वाले तीन लोगों पर मधुबन बापूधाम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दो साल पहले जीडीए कालोनी में ध्वस्तीकरण भी करा चुका है। फिर भी कॉलोनाइजर कॉलोनी में भूखंड का सौदा करते रहे।

जीडीए प्रवर्तन जोन-तीन के अवर अभियंता राजेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मटियाला रोड पर जनहित इंस्टीट्यूट के पास दो साल से कॉलोनी काटी जा रही है। कॉलोनाइजर आबिद, अतीक और इंद्रपाल कॉलोनी काटकर भूखंड बेच रहे हैं।

जीडीए तीन बार कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है फिर भी निर्माण जारी है और कॉलोनाइजर भूखंड बेच रहे हैं।

जीडीए ने अवैध कॉलोनियों की सूची जारी की

अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का दावा करने वाले जीडीए के क्षेत्र में 350 अवैध कॉलोनियां हैं। करीब 100 कॉलोनियां ऐसी हैं जो दो वर्ष के अंदर बनी हैं। जीडीए लगातार कार्रवाई का दावा करता रहा और कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काटते रहे। 96 कॉलोनी ऐसी हैं जिनका नाम जीडीए को न पता है।

न्यू करहैड़ा कॉलोनी है सबसे बड़ी

जीडीए क्षेत्र में सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी 10 साल पहले बनी न्यू करहैड़ा कॉलोनी है। इसका क्षेत्रफल करीब 250 एकड़ है, जबकि हिंडन विहार कॉलोनी का क्षेत्र 125 एकड़ है। महिंद्रा एंक्लेव कॉलोनी करीब 40 एकड़ में बनी हुई है।

दुनिया के हर कोने तक पहुंचेंगे नोएडा में बने खिलौने, एनसीआर के हजारों लोगों को मिलेगी

नोएडा के टॉय पार्क में बने खिलौनों दुनिया भर के बाजारों में बिकेंगे। नोएडा में बन रहा टॉय पार्क भारत को खिलौनों के वैश्विक बाजार में अग्रणी बनाएगा। अगले दो साल में 134 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। एजुकेशन टॉय से लेकर सॉफ्ट टॉय तक बनेंगे। इसके विकसित होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ग्रेटर नोएडा। खिलौनों की वैश्विक दुनिया में भारत की धाक जमाने के लिए यमुना प्राधिकरण में विकसित हो रहे टाय पार्क की अहम भूमिका होगी। अगले दो साल में टाय पार्क की 134 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। कुछ इकाइयों का निर्माण जारी है। इसमें साल के अंत तक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

टाय पार्क में एजुकेशन टाय से लेकर साफ्ट खिलौने बनाए जाएंगे, जो दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे। यमुना प्राधिकरण ने भारतीय खिलौना उद्योग को मजबूती देने के लिए टाय पार्क की योजना तैयार की थी। सेक्टर 33 में 100 एकड़ में खिलौना पार्क के लिए 134 भूखंडों का आवंटन हुआ था।

इसमें कितने प्लॉटों की हो चुकी है रजिस्ट्री?

इसमें एक हजार वर्गमीटर से लेकर 10,500 वर्गमीटर के भूखंड शामिल हैं। इसमें से 94 भूखंडों की रजिस्ट्री हो चुकी है। कई आवंटियों ने मानचित्र स्वीकृत कराने के साथ निर्माण भी शुरू कर दिया है।

वहीं, इस साल के अंत तक इन इकाइयों में खिलौनों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस बारे में खिलौना पार्क के समन्वयक एवं उद्यमी नरेश गुप्ता का कहना है कि अगले दो साल में खिलौना पार्क में सभी इकाइयां बनकर तैयार हो जाएंगी। इसके साथ ही यहां से खिलौनों का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।

हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार

खिलौना पार्क का सबसे अधिक फायदा नौकरी की तलाश करने वालों के लिए होगा। खिलौना पार्क में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। खासकर महिलाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। जो महिलाएं अधिक शिक्षित नहीं है, वह भी थोड़े से प्रशिक्षण के बाद आजीविका प्राप्त कर सकेंगी।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा विकसित

खिलौना पार्क में पांच एकड़ कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित होगा। इसमें खिलौनों की प्रदर्शनी से लेकर उनके डिजायन, रिसर्च, विपणन, आधुनिक मशीनरी आदि होगी। इसका सीधा फायदा खिलौना पार्क में विकसित होने वाली इकाइयों को मिलेगा।

एजुकेशन से लेकर सॉफ्ट खिलौनों का होगा उत्पादन

खिलौना पार्क में एजुकेशन से लेकर सॉफ्ट खिलौनों का उत्पादन होगा। इसमें कपड़े से लेकर लकड़ी के खिलौने बनाए जाएंगे, जिससे बच्चों को खेलने के साथ साथ सीखने का मौका भी मिलेगा।

यीडा क्षेत्र में कहां बन रहा खिलौना पार्क?

इस संबंध में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यीडा क्षेत्र के सेक्टर 33 में खिलौना पार्क विकसित हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण खिलौनों को यहां से दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना आसान होगा।

आवंटियों ने भूखंडों पर कब्जा मिलने के बाद इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है। इस साल के अंत तक यीडा क्षेत्र में खिलौनों का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

सब्जी के बाद BJP विधायक ने बेचे बर्तन, आखिर पैठ बाजार को लेकर पुलिस से क्यों छिड़ी है जंग?

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के आदेश के बावजूद पुलिस ने मंगल बाजार चौक पर लोगों को पैठ लगाने से रोका। विधायक ने कहा ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस दौरान बर्तन भी बेचे।

साहिबाबाद। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के नीति खंड स्थित मंगल बाजार चौक पर पैठ बाजार लगाने पहुंचे दुकानदार को पुलिस ने रोक दिया। दुकानदारों ने मुख्य सचिव के आदेश का हवाला देते हुए विरोध किया।

आरोप है कि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। बाजार हटने की सूचना पर लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर पहुंचे। उन्होंने बाजार लगवाया और बर्तन बेचे। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि लाठी मारने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो।

पैठ बाजारों को कर दिया था बंद

जिले में मुख्य सड़क पर पैठ बाजार लगने के कारण जाम की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही थी। पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची थी। पुलिस ने मुख्य मार्गों पर लगने वाले पैठ बाजारों को बंद कर दिया था। इसका जमकर विरोध हुआ था।

मुख्य सचिव ने दिया था ये आदेश

वहीं, गाजियाबाद पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए यथा स्थिति बाजार लगने के आदेश दिए थे। मंगलवार को इंदिरापुरम के नीति खंड में मंगल चौक पर व्यापारी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बाजार लगाने पहुंचे थे। कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची।

आरोप है कि पुलिस ने बाजार बंद कराना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने इसका विरोध कर दिया। मुख्य सचिव के आदेश का हवाला दिया। आरोप है कि दुकानदारों को खदेड़ा गया। पैठ बाजार बंद कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो देखकर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर शाम करीब साढ़े सात बजे इंदिरापुरम पहुंचे।

कार्रवाई का विरोध किया और फिर से बाजार लगवा दिया

उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया और फिर से बाजार लगवा दिया। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मुख्य सचिव ने साप्ताहिक बाजारों को पुराने स्थानों पर लगाने के आदेश दिए थे। पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करने से मना किया था।

इसके बाद भी पुलिस मुख्य सचिव के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही है। साप्ताहिक बाजार पहले की तरह लगते रहेंगे। विधायक ने लाठी मारने की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। यदि अब कहीं पैठ बाजार लगने से पुलिस रोकती है तो वह आलाधिकारियों के घर के बाहर सब्जी बिकवाएंगे। इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

इस मामले के लिए पुलिस का पक्ष जानने के लिए पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन को कॉल की गई, वाट्सएप पर संदेश भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

दो दुकानदारों की आर्थिक मदद की

पैठ बाजार में दुकान लगाने पहुंचे महीपाल सिंह का कहना था कि वह कैंसर पीड़ित है। दुकान लगाकर अपना इलाज और परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। दुकान नहीं लगने से उसके आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वीडियो प्रसारित होने के बाद मौके पर पहुंचे विधायक लोनी नंद किशोर गुर्जर ने उनकी व एक दिव्यांग दुकानदार की आर्थिक मदद की।

आधुनिक विकास की आंधी में भारतीय संस्कृति सभ्यता विरासत पुरातत्वों को बचाना अत्यंत ज़रूरी

भारतीय विज़न 2047 के विकास पथ में विकास के साथ संस्कृति व विरासत पर ज़ोर देना समय की मांग

युवाओं को भारतीय संस्कृति, सभ्यता विरासत पांडुलिपि कला, प्रथाओं धरोहर स्मारक के प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत ज़रूरी

–एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियां के हर देश में विकास की एक आंधी सी चल रही है। हर देश वैश्विक वित्तीय मंचों संस्थाओं से अपने देश के लिए धन आवंटित कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि अपने देश को आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ा सकें।भारत ने भी अपना विज़न 2047 रूपी विकसित भारत का विकासपत्र तैयार किया है, जिसमें आगे बढ़ाने की प्लान हमने पूर्ण बजट 1 फ़रवरी 2025 में भी देखें। परंतु इस बजट में ध्यान देने योग्य बात यह है कि माननीय वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में देश के विकास पथ में विकास और विरासत दोनों पर सरकार के जोर को रेखांकित किया जो ध्यान देने योग्य बात है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 3360.96 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मंत्रालय के भीतर, एक बड़ा हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गया है,जिसे 2024- 25 में आवंटित 1273.91 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,278.49 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे संशोधित कर 1191.99 करोड़ रुपये कर दिया गया था.सरकार कल्चरल डेवलपमेंट तो चाहती है, लेकिन इसने शताब्दी और वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन में होने वाले बजट में बहुत कमी कर दी है, इन आयोजनों के लिए बजट 2024-25 में 110 करोड़ रुपये से घटाकर 2025-26 में सिर्फ 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ और अहिल्या बाई होल्कर की 300 वीं जयंती जैसे प्रमुख समारोह अभी भी सरकार के समर्थन से मनाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग के लिए निर्धारित धनराशि में तीव्र गिरावट देखी गई है। 2024-25 में 10.50 करोड़ रुपये से 2025-26 में 4.65 करोड़ कर दी गई है एएसआई वह एजेंसी है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सहित 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, संरक्षण और विकास का कार्य सौंपा गया हैअन्य आवंटनों के अलावा, राष्ट्रीय पुस्तकालयों और अभिलेखागार के लिए 156.55 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं,जो ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं।राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी जैसे संग्रहालयों को सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए 126.63 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. प्राचीन लिपियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन को 60 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है।इस बीच, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 22.46 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के तहत सांस्कृतिक गतिविधियों को समेकित करना है।सरकार संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जैसे स्वायत्त सांस्कृतिक संस्थानों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।इन निकायों को सामूहिक रूप से 411.42 करोड़ रुपये मिलेंगे, इसके अतिरिक्त, विक्टोरिया मेमोरियल और भारतीय संग्रहालय सहित संग्रहालयों को उनके प्रदर्शन और आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए 379.58 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हमें भारत की पौराणिक व पारंपरिक संस्कृति विरासत पांडुलिपि धरोहर स्मारकों को सहेज कर रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी, युवाओं को जागरूक करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार ने भी मेरा गांव मेरी धरोहर, भारतीय संस्कृति व विरासत के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने व राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन तथा राष्ट्रीय संस्कृति कोष जैसी योजनाएं चल रहा है।चूंकि आधुनिक विकास की आंधी में भारतीय संस्कृति विरासत पुरातत्व पांडुलिपि को बचाना अत्यंत जरूरी है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारतीय विज़न 2047 के पथ में विकास के साथ संस्कृति व विरासत पर जोर देना समय की है, व युवाओं को भारतीय संस्कृति, विरासत, पांडुलिपि कला प्रथाओं धरोहर स्मारक के प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत ज़रूरी है।

साथियों बात अगर हम केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर योजना की करें तो,कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता योजना का विवरण और योजना के लिए आवंटित धन का विवरणइस योजना में निम्नलिखित उप- घटक हैं वे,(1) राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता इस योजना घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में शामिल राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। यह अनुदान ऐसे संगठनों को दिया जाता है जिनके पास उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय है, जो भारत में पंजीकृत है; इसके संचालन में राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ अखिल भारतीय चरित्र होना; पर्याप्त कार्य शक्ति; और पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों पर 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक खर्च किये हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुदान की मात्रा 1.00 करोड़ रुपये है जिसे असाधारण मामलों में 5.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। (2) सांस्कृतिक समारोह एवंउत्पादन अनुदान इसयोजना घटक का उद्देश्य संगोष्ठी, सम्मेलन अनुसंधान कार्यशालाओं त्यौहारों प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, नृत्य, नाटक थिएटर, संगीत आदि के उत्पादन के लिए गैर सरकारी संगठनोंसोसाइटियों/ट्रस्टों/विश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत एक संगठन के लिए अनुदान 5 लाख रुपये है जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। असाधारण मामलों में 20.00 लाख रुपये हो सकता है। (3) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायताइस योजना घटक का उद्देश्य ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है।हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों यानी जम्मू और कश्मीर,हिमाचल प्रदेशउत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। (4) बौद्ध तिब्बती संगठन के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती सांस्कृतिक और परंपरा के प्रचार-प्रसार और वैज्ञानिक विकास और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना घटक के अंतर्गत वित्त पोषण की मात्रा एक संगठन के लिए प्रति वर्ष 30.00 लाख है, जिसे असाधारण मामलों में 1.00 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। (5) स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान के लिए वित्तीय सहायता।इसयोजना घटक का उद्देश्य एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटी, सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना घटक के तहत सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे (यानी स्टूडियो थिएटर, ऑडिटोरियम, रिहर्सल हॉल, कक्षा आदि) के निर्माण और बिजली, एयर कंडीशनिंग, ध्वनिकी, प्रकाश और ध्वनि प्रणाली आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के लिए प्रायोजित निकाय,विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि। अनुदान की अधिकतम राशि मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपये तक और गैर- मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपये तक है। (6) संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायताइस योजना घटक का उद्देश्य नियमित आधार पर और खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों में त्योहारों के दौरान सजीव प्रदर्शन का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ऑडियो-विजुअल तमाशा को बढ़ाने के लिए संपत्ति के निर्माण के लिए सभी पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। (7) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजनाःयह योजना 2013 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों, समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि को पुनर्जीवित करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि वे गतिविधियों परियोजनाओं में संलग्न हो सकें। भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना, सुरक्षा करना, संरक्षित करना और बढ़ावा देना।यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

साथियों बात अगर हम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय संस्कृति और विरासत के जनजागरण अभियान के तहत योजनाओं की करें तो संयह निरंतर प्रयास रहा है कि देश के युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों में भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तदनुसार, मंत्रालय युवाओं के लिए योजनाएं संचालित करता है जैसे कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करना, जिनका विवरण इस प्रकार है (i) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः एक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत, 18-25 वर्ष की आयु के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत,भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंचमूकाभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कला और सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 5,000/- रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्रवृत्ति की धनराशि चार बराबर छह मासिक किश्तों में जारी की जाती है। (7) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। ये जेडसीसी पूरे वर्ष देश भर में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके लिए उन्हें वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कलाकारों को जेडसीसी द्वारा लगाया जाता है, वर्ष 2015 से अब तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में चौदह क्षेत्रीय उत्सव तथा चार क्षेत्रीय उत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। ये क्षेत्रीय उत्सव कला एवं संस्कृति के विकास के लिए हर वर्ष कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सव भी आयोजित करते हैं।संस्कृति मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को उनकी विभिन्न पहलों/ कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक सहायता प्रदान करता है। इसलिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में हमारी समृद्ध संस्कृति एवं विरासत के अध्यायों को शामिल करने के लिए कोई अलग कदम नहीं उठाया गया है।केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। देश में प्रचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवेश अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीयमहत्व के रूप में घोषित 3697 प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल हैं। स्मारकों की राज्य-वार संख्या तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इनस्मारकों और स्थलों के संरक्षण परिरक्षण तथा रख-कखाव पर किया गया व्य अनुबंध में दिया गया है।संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों का संरक्षण, परिरक्षण तथाअनुरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है और तदनानुसार इसके लिए निश्चित निधियां आवंटित की जाती हैं।सुरक्षा और संरक्षण तथा पर्यटक सुविधाएं/अवसंचरना उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्मारकों की पहचान करना एक नियमित प्रक्रिया है। तमिलनाडु के स्मारकों के लिए निर्गत आवंटन निम्नानुसार है।यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय संस्कृति कोष की करें तो,सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापन भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पूर्त विन्यास अधिनियम 1980 के अंतर्गत 28 नवंबर 1996 को एक न्यास के रुप में की थी।राष्ट्रीय संस्कृति निधि हेतु अशंदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (ii) के अंतर्गत कर में 100 फीसदी छूट के लिए पात्र हैं।

साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की करें तो इसके मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण औरऑनलाइन प्रसार करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मिशन ने पूरे भारत में 100 से अधिक पांडुलिपि संसाधन केन्द्र और पांडुलिपि संरक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।यह जानकारी केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आधुनिक विकास की आंधी में भारतीय संस्कृति,सभ्यता विरासत पुरातत्व पांडुलिपि को बचाना अत्यंत ज़रूरी।भारतीय विज़न 2047 के विकास पथ में विकास के साथ संस्कृति व विरासत पर ज़ोर देना समय की मांग।युवाओं को भारतीय संस्कृति,सभ्यता विरासत पांडुलिपि कला,प्रथाओं धरोहर स्मारक के प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत जरूरी है।

खरीदकर लानी है महिंद्रा की थार रॉक्स एसयूवी, बुकिंग करवाने से पहले जान लें कितने महीने का है प्रतीक्षा अवधि

परिवहन विशेष न्यूज

Mahindra thar roxx waiting period भारतीय बाजार में Mahindra की ओर से कई बेहतरीन एसयूवी को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra की ओर से ऑफर की जाने वाली Thar Roxx पर कितने महीने की Waiting चल रही है। फरवरी में बुक करवाने के बाद इसकी डिलीवरी कब तक मिल सकती है। किस वेरिएंट पर सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में दमदार इंजन और फीचर्स के साथ कई सेगमेंट में एसयूवी को ऑफर करने वाली वाहन निर्माता Mahindra की Thar Roxx को घर लाने के लिए लंबा इंतजार (thar roxx waiting period) करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के किस वेरिएंट के लिए सबसे ज्यादा Waiting Period चल रहा है। फरवरी में बुक करवाने के बाद कब तक इसकी डिलीवरी मिल सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra Thar Roxx पर है लंबा इंतजार

महिंद्रा की ओर से ऑफर की जाने वाली एसयूवी Mahindra Thar Roxx को खरीदकर घर लाने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लॉन्च के बाद से ही इस एसयूवी के लिए बड़ी संख्या में बुकिंग किए जाने के कारण लंबा Waiting Period चल रहा है।

कितना करना होगा इंतजार

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से डीलर्स को वेटिंग पीरियड से जुड़ी जानकारी दी गई है। जिसके मुताबिक एसयूवी के अलग अलग वेरिएंट पर अलग अलग वेटिंग चल रही है। एसयूवी के लिए अधिकतम 18 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

किस वेरिएंट पर कितनी है वेटिंग

जानकारी के मुताबिक एसयूवी के बेस वेरिएंट MX1 को पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लाया जाता है। एसयूवी के बेस वेरिएंट के दोनों इंजनों के लिए सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इस पर अधिकतम 18 महीने का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा एसयूवी के टॉप वेरिएंट AX7L 4X4, Diesel MT, AT पर भी 18 महीने तक की वेटिंग चल रही है।

Mahindra Thar Roxx के मिड वेरिएंट के तौर पर MX3, AX3L, MX5 और AX5L को लाया जाता है। इन वेरिएंट्स के लिए भी करीब छह महीने तक की वेटिंग चल रही है। वहीं AX7L 4X2 वेरिएंट के लिए अधिकतम 10 महीने की वेटिंग चल रही है।

कंपनी बढ़ा चुकी है उत्पादन

लॉन्च के साथ ही एसयूवी के लिए कंपनी को लाखों की संख्या में बुकिंग मिली थीं। जिसके बाद इसके लिए लंबी वेटिंग हो गई थी। इसे देखते हुए कंपनी ने फैसला किया था कि वह इसके उत्पादन को बढ़ाकर वेटिंग पीरियड को कम करेगी। जिसके बाद उत्पादन में बढ़ोतरी की गई, लेकिन फिर भी एसयूवी के लिए लगातार बढ़ती बुकिंग के कारण वेटिंग पीरियड कम नहीं हो रहा।

कितनी है कीमत

महिंद्रा की ओर से Thar Roxx को कुल छह वेरिएंट्स के विकल्प के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 23.09 लाख रुपये है। एसयूवी को पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 4X2 और 4X4 के विकल्प के साथ लाया जाता है।

वोल्वोकर रही XC90 फ़ेसलिफ़्ट को भारत में लॉन्च करने की तैयारी, जानें कब आएगी, क्या हो सकता है बदलाव

परिवहन विशेष न्यूज

वोल्वो XC90 फेसलिफ्ट2025 यूरोप की वाहन निर्माता Volvo की ओर से बेहद सुरक्षित और बेहतरीन फीचर्स वाली कारों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से जल्द ही नई गाड़ी को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। किस गाड़ी को किस तरह के फीचर्स के साथ कब तक लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। स्वीडन की प्रमुख वाहन निर्माता Volvo की ओर से कई सेगमेंट में Cars And SUVs को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से जल्द ही नई गाड़ी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। किस सेगमेंट में किस तरह के फीचर्स के साथ कब तक नई गाड़ी को लॉन्च (upcoming Volvo cars) किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च होगी नई गाड़ी

Volvo की ओर से जल्द ही नई गाड़ी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से अभी औपचारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि वह किस गाड़ी को लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रीमियम एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Volvo XC90 के Facelift को बाजार में लाया जा सकता है।

ग्लोबल स्तर पर हो चुकी है पेश

कंपनी की ओर से इस एसयूवी को साल 2024 के सितंबर महीने में ही ग्लोबल स्तर पर पेश किया जा चुका है। जिसके बाद अब इस एसयूवी के फेसिलफ्ट को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है।

क्या होगा बदलाव

जानकारी के मुताबिक एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर में भी कई बदलाव होंगे और कुछ नए फीचर्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा। एसयूवी के फेसलिफ्ट में नए डिजाइन वाली ग्रिल, टी-शेप एलईडी डीआरएल, नई हेडलाइट्स को दिया जाएगा। इसके अलावा साइड और रियर प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव की उम्मीद कम है। इंटीरियर में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ही फोर जोन ऑटो एसी, पैनोरमिक सनरूफ जैसे कुछ नए फीचर्स को जोड़ा जा सकता है।

कितना दमदार होगा इंजन

Volvo XC90 एसयूवी में कंपनी की ओर से दो लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया जाएगा। जिसके साथ 48V माइल्ड हाइब्रिड या प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक को दिया जा सकता है। माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ इसे 250 पीएस की पावर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। वहीं प्लग-इन तकनीक के साथ एसयूवी को 455 पीएस की पावर और 709 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ एसयूवी में 8स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को दिया जाएगा और इसमें ऑल व्हील ड्राइव को भी ऑफर किया जाएगा।

कब होगी लॉन्च

Volvo XC90 के Facelift को भारतीय बाजार में चार मार्च 2025 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के समय इसकी एक्स शोरूम कीमत एक करोड़ रुपये के आस-पास हो सकती है। बाजार में इसका मुकाबला Mercedes Benz GLE, BMW X5, Audi Q7 और Lexus RX जैसी एसयूवी के साथ होगा।

स्कोडा भी करेगी ई.वी सेगमेंट में एंट्री, कब तक ला सकती है पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, पढ़ें पूरी खबर

स्कोडा इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च भारत में Electric Vehicle सेगमेंट का बाजार लगातार बढ़ रहा है। जिसे देखते हुए कई वाहन निर्माता अपने उत्पादों को लॉन्च और पेश कर रही हैं। यूरोप की प्रमुख वाहन निर्माता Skoda की ओर से भी EV सेगमेंट में आने की तैयारी की जा रही है। कंपनी कब तक अपनी पहली Electric SUV को भारत में लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। चेक रिपब्लिक की वाहन निर्माता Skoda की ओर से भारत में ICE सेगमेंट में कई बेहतरीन एसयूवी और कारों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से अब पहली EV के तौर पर Electric SUV को लाने की तैयारी की जा रही है। स्कोडा कब तक देश में अपनी पहली EV ला सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Škoda कर रही पहली EV लाने की तैयारी

स्कोडा की ओर से भारत में पहली EV को लाने की तैयारी (Škoda EV India Launch) की जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी की ओर से Bharat Mobility के तहत आयोजित हुए Auto Expo 2025 में भी EV एसयूवी को शोकेस किया गया था।

किस Electric SUV से होगी शुरुआत

स्कोडा की ओर से अभी यह तय नहीं किया गया है कि किस एसयूवी को इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Škoda Enyaq को पहली Electric SUV के तौर पर लाया जा सकता है। इसके अलावा भी कंपनी Elroq, Enyaq और Enyaq Coupe को भी भविष्य में पेश (Škoda Expected EVs in India) कर सकती है।

कब तक आ सकती है एसयूवी

जानकारी के मुताबिक स्कोडा अभी केंद्र सरकार की ईवी पॉलिसी का इंतजार कर रही है। मार्च-अप्रैल में स्थिति साफ होने के बाद ही Škoda तय करेगी किस किस एसयूवी को लाया जाएगा। लेकिन यह साफ है कि इस साल फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले सितंबर महीने में ही Skoda की ओर से पहली Electric SUV को लाया जाएगा।

ICE सेगमेंट में भी कई कारें हो सकती हैं पेश

स्कोडा के लिए भारत बड़ा बाजार है। ऐसे में कंपनी की ओर से EV के साथ ही ICE सेगमेंट में भी कई कारों को लाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक साल के मध्य तक Skoda Kodiaq की नई जेनरेशन को लाया जा सकता है। इस एसयूवी को सीकेडी के तौर पर भारत लाया जाएगा। इसके अलावा Skoda Octavia RS को भी सीमित संख्या में सीबीयू के तौर पर लाया जा सकता है।

Skoda ने हाल में लॉन्च की है Kylaq

स्कोडा की ओर से छह नंबवर 2024 को भारत में Sub Four Meter SUV के तौर पर Kylaq को लॉन्च किया गया था। इस एसयूवी को लॉन्च के बाद से काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही यह एसयूवी स्कोडा की ओर से ऑफर की जाने वाली सबसे सस्ती एसयूवी है, जिसे 7.89 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया गया था।

हुंडई कर रही नई जनरेशन क्रेटा की तैयारी, नई तकनीक के साथ कब तक हो सकती है लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Mid Size SUV सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Hyundai Creta को काफी पसंद किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस एसयूवी की New Generation को लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की ओर से इसे कब तक लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

आएगी Hyundai Creta New Generation

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई की ओर से नई जेनरेशन क्रेटा को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है।

मिल सकता है Hybrid तकनीक वाला इंजन

जानकारी के मुताबिक कंपनी की ओर से नई जेनरेशन क्रेटा को सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटिड और टर्बो इंजन के साथ ही नहीं लाया जाएगा। बल्कि एसयूवी की नई जेनरेशन में हाइब्रिड तकनीक वाले इंजन को भी ऑफर किया जा सकता है। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता के पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड तकनीक को दिया जा सकता है।

2024 में मिला था अपडेट

हुंडई की ओर से क्रेटा को 2024 में अपडेट किया गया था। 2024 की जनवरी में ही इस एसयूवी को नए लुक्स और कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लाया गया था। जिसके कुछ समय बाद इसके ज्यादा स्पोर्टी वर्जन N Line को भी अपडेट के साथ लाया गया था। इस साल जनवरी महीने में Bharat Mobility के तहत आयोजित किए गए Auto Expo 2025 में भी इस एसयूवी के Electric वर्जन को लॉन्च किया गया था।

नई जेनरेशन में होंगे ये बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक New Generation Hyundai Creta को SX3 कोडनेम के साथ डेवलप किया जा रहा है। नई जेनरेशन क्रेटा में कई बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही इसमें मौजूदा वर्जन के मुकाबले ज्यादा बेहतर फीचर्स (Creta Next Generation Features) और डिजाइन को दिया जा सकता है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में भी ज्यादा बड़ी बैटरी और दमदार मोटर को लाया जा सकता है।

कब तक हो सकती है लॉन्च

हुंडई की ओर से इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नई जेनरेशन हुंडई क्रेटा को साल 2026 के आखिर या 2027 तक पेश (Creta Next Generation Launch Date) किया जा सकता है। इस एसयूवी का प्रोडक्शन भारत के तमिलनाडु में मौजूद फैक्ट्री से ही किया जा सकता है।

किनसे है मुकाबला

Hyundai Creta को कंपनी की ओर से Mid Size SUV सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Kia Seltos, Mahindra Scorpio N, XUV 700, JSW MG Hector और Astor जैसी एसयूवी के साथ होता है।

टाटा कर रही नेक्सन में बड़े बदलाव की तैयारी, मारुति, महिन्द्रा, किआ स्कोडा को मिलेगी कड़ी चुनौती

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। कंपनी की ओर से जल्द ही Sub Four Meter SUV के तौर पर ऑफर की जाने वाली Tata Nexon में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी की ओर से किस तरह के बदलाव एसयूवी में किए जा सकते हैं। इससे किनको चुनौती मिलेगी। कब तक इसे लाया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट में कई बेहतरीन वाहनों को ऑफर करने वाली Tata Motors की ओर से Nexon में बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस Sub Four Meter SUV में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। कब तक नई Tata Nexon को लाया जा सकता है। इससे किस कंपनी की कौन सी एसयूवी को चुनौती मिलेगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Nexon में होंगे बड़े बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की ओर से Nexon एसयूवी में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी की ओर से इस एसयूवी की नई जेनरेशन को लाने की तैयारी की जा रही है।

क्या होंगे बदलाव

जानकारी के मुताबिक एसयूवी को बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनाने की जगह मौजूदा प्लेटफॉर्म X1 में कुछ बदलावों के साथ सेकेंड जेनरेशन Tata Nexon को लाया जा सकता है। जिसे इंटरनली गरुड़ नाम दिया गया है। इसमें कई बड़े बदलावों के साथ ही स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा।

मौजूदा वर्जन में भी हुए हैं बदलाव

कंपनी की ओर से नेक्सन की मौजूदा वर्जन में भी समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं। इसमें 2020 और 2023 में कई बदलाव किए गए थे। 2018 में इसे व्यस्कों की सुरक्षा के लिए पांच और बच्चों की सुरक्षा के लिए Global NCAP की ओर से तीन स्टार मिले थे, लेकिन लगातार हुए बदलावों का यह फायदा हुआ कि इसे 2024 में हुए क्रैश टेस्ट में एसयूवी को व्यस्कों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए पूरे पांच स्टार हासिल हुए थे।

मिल सकते हैं नए फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की नई जेनरेशन के लॉन्च के समय इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें पैनोरमिक सनरूफ, Level-2 ADAS, एंबिएंट लाइट्स सहित एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी कई फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है।

क्या इंजन में होगा बदलाव?

कंपनी की ओर से इसमें 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और सीएनजी इंजन दिया जाता है। साथ ही इसमें अभी डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है। लेकिन नई जेनरेशन में डीजल इंजन के विकल्प की जगह अन्य तकनीक को दिया जा सकता है।

कब होगी लॉन्च

टाटा की ओर से अभी इस बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कंपनी की ओर से नई जेनरेशन टाटा नेक्सन को भारत में साल 2026 के आखिर या 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।

किनसे होगा मुकाबला

Tata Nexon को Sub Four Meter एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में Maruti Breeza, Hundai Venue, Kia Sonet और Kia Syros, Mahindra XUV 3XO और Skoda Kylaq जैसी एसयूवी को ऑफर किया जाता है। इन सभी में कई बेहतरीन फीचर्स, तकनीक को दिया जा रहा है। ऐसे में टाटा की ओर से नई नेक्सन का सीधा मुकाबला इन सभी एसयूवी के साथ होगा।

छात्रों के लिए पुस्तक मेले का महत्व

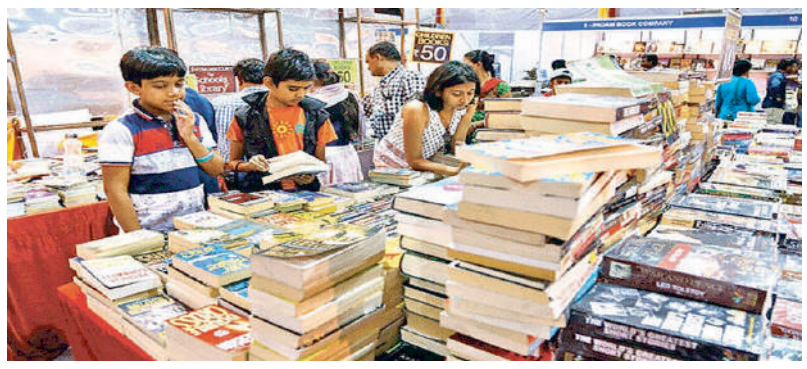

विजय गर्ग

सीखना मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो उनके विकास की सुविधा प्रदान करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को अपनाना होगा और पुस्तक मेले असीमित लाभ प्रदान करते हैं। एक पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए ब्राउज़ करने और खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के प्रदर्शन के साथ एक सभा है। लेखकों को अपने प्रशंसकों से मिलने का अवसर मिलता है। पुस्तक मेले एक छात्र के जीवन के लिए कई लाभ प्रदान करते हैं। सबसे पहले, एक पुस्तक मेला उन पुस्तकों की दावत प्रदान करता है जो एक छात्र को प्रेरित करती हैं। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की उपस्थिति पुस्तकों के साथ एक आकर्षण और पढ़ने में रुचि पैदा करती है। छात्र एक मेले में चल सकते हैं, विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से ब्राउज़ कर सकते हैं, और उन विषयों को चुन सकते हैं जो उन्हें सबसे अधिक लुभाते हैं। कविताओं, इतिहास पर किताबें, भूगोल, कला, संस्कृति, उपन्यास, रसोई की किताबें और कहानियों जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की उपस्थिति, एक छात्र के पढ़ने और सीखने में विविधता लाती है। इस प्रकार, यह उन्हें अपने स्कूल के अनुभव में विभिन्न विषयों और कक्षाओं के लिए खुला और समायोजित करता है। इसके अलावा, भविष्य में लेखक बनने के इच्छुक छात्रों के लिए, मेले अपने सपने के प्रति प्रेरणा के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं; पुस्तकों के प्रकाशन और पसंदीदा लेखकों से तेजी से हाथ प्रेरणा प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखें। दूसरे, पुस्तक मेले पढ़ने के लिए प्यार पैदा करते हैं जो हमेशा के लिए रहता है। किताबें एक व्यक्ति का एक अभिन्न हिस्सा हैं क्योंकि वे कंपनी प्रदान करते हैं, किसी के हितों का उच्चारण करते हैं और एक अच्छे दोस्त हैं। पुस्तक मेलों में भाग लेने से प्राप्त जोखिम पुस्तकों की विभिन्न सरणी, जीवन में अंतर्दृष्टि, सलाह, मनोरंजन, जीवन और दुनिया के अन्य विषयों के माध्यम से एक पूरी नई दुनिया तक पहुंच के माध्यम से है। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान और व्यापक जानकारी नियमित रूप से पढ़ने की इच्छा और रुचि को प्राप्त करती है। इसलिए, एक छात्र एक नियमित पाठक बन जाता है जो उनकी सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पुस्तक मेले छात्रों को नई चीजों के लिए उजागर करते हैं। पुस्तकों का पढ़ना एक छात्र को खोजों, नई जानकारी, विचारों और सोचने का एक तरीका प्रस्तुत करता है जो समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इनके साथ, एक छात्र अपने जीवन में उत्पन्न मुद्दों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हो जाता है, अधिक पुस्तकों का उपयोग करता है जो शैक्षिक अवधारणाओं की उनकी समझ को आसान बनाता है जो उन्हें नए शौक और हितों को विकसित करने में असाधारण छात्र और सहायक बनाता है। इसके अलावा, मेले उन्हें प्रकाशन, विपणन और रचनात्मक लेखन की दुनिया में उजागर करते हैं। छात्रों की कल्पना पुस्तक मेलों के माध्यम से फैलती है। किसी व्यक्ति की क्षमताओं की सीमा उनके दृश्य के माध्यम से होती है। मेलों में सुलभ विविध पुस्तकें विभिन्न दुनिया में गहराई से अंतर्दृष्टि का वर्णन करती हैं और प्रदान करती हैं कि कोई व्यक्ति परिचित नहीं है। तदनुसार, वे विभिन्न दुनिया का वर्णन करने वाली पुस्तकों की एक अलग सरणी पेश करके, छात्रों की कल्पना के विस्तार के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। एक विस्तारित कल्पना के माध्यम से, छात्रों की रचनात्मकता स्कूली काम में परियोजनाओं के लेखन, डिजाइन, कला और विकास में अपनी रचनात्मकता में सुधार को व्यापक बनाती है। पुस्तक मेले एक छात्र की स्मृति को बढ़ावा देते हैं। जब कोई छात्र पुस्तकों के निरंतर पढ़ने में संलग्न होता है, तो उन्हें सोच को प्रेरित करने के लिए अधिक जानकारी और विचार मिलते हैं, इसे सक्रिय रखने के लिए मस्तिष्क में समझ और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का वातावरण बनाता है। नतीजतन, यह स्मृति को तेज करने और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के परिणामस्वरूप होता है जो एक छात्र को आसानी से कक्षा में सीखी गई अधिक शैक्षिक सामग्रियों को पकड़ने और याद रखने की क्षमता में परिणाम देता है, और उनके परीक्षण लेने के कौशल में सुधार करता है। पुस्तक मेलों के माध्यम से, एक छात्र उन पुस्तकों तक पहुंच सकता है जो प्रिंट का पता लगाना या बाहर करना मुश्किल है। त्योहार पुस्तकों के प्रति उत्साही, लेखक और प्रकाशकों को पुस्तकों के हित में एक साथ लाते हैं। इसलिए, जब एक छात्र को एक पुस्तक में रुचि होती है जिसे एक्सेस करना कठिन होता है, तो लेखक या प्रकाशक इसे संभव बनाने में काम आते हैं। पुस्तक मेले छात्रों को पुस्तकों तक पहुंच से अधिक प्रदान करते हैं। वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के लिए उजागर करते हैं, उन्हें पसंदीदा लेखकों से जोड़ते हैं, पढ़ने और उन्हें प्रेरित करने में उनके हितों का विकास करते हैं। इसलिए, छात्रों को पुस्तक मेलों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए।

उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ, भू -राजनीतिक गठबंधन विकसित करना

विजय गर्ग

उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक जहां दृश्यमान परिवर्तनों को जनवरी 2025 के बाद देखा जाएगा, यह संचार परिदृश्य भूवैज्ञानिक रूप से है। यह युग वैश्विक संचार के बहुत स्पीडवे को फिर से परिभाषित करने के लिए तैनात है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथः क्या हम संचार वितरण, सामग्री अभिविन्यास, आउटरीच तंत्र और उपकरणों में 360-डिग्री परिवर्तन के कगार पर हैं? भूवैधानिक रूप से, संचार पारिस्थितिकी तंत्र एक नई भाषा को गले लगाएगा-जो कि केंद्रित संदेश, परिणाम-चालित वितरण, और यथार्थवादी पैटर्न और वैश्विक प्रभावों की पहचान करने के लिए औसत दर्जे के परिणामों की प्राथमिकता है। जैसा कि दुनिया भू -राजनीतिक बदलाव के इस नए अध्याय में कदम रखती है, संचार रणनीतियाँ अधिक परिष्कृत, गतिशील और बहुआयामी होती जा रही हैं। घंटे की आवश्यकता यह है कि नए गठजोड़ को स्थानांतरित करने वाले राजनीतिक परिदृश्य और प्रमुख भू -राजनीतिक विकास में शामिल किया जाए। विकसित होने वाली राजनीतिक जलवायु पारंपरिक प्रतिमानों को चुनौती दे रही है, संचार विशेषज्ञों, राजनयिकों और नीति निर्माताओं को यह पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है कि संदेश कैसे तैयार किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, और एक वैश्विक मंच पर प्राप्त किए जाते हैं। ईआरए एक संचार ढांचे की मांग करता है जो न केवल सीमाओं को स्थानांतरित करता है, बल्कि पुल भी सटीक, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ विभाजित करता है। 2025 में, ₹एक चित्र एक हजार शब्दों के लायक है₹ वाक्यांश अधिक अनुनाद पर ले जाता है। संदेश देने के लिए दृश्य संचार सबसे प्रभावशाली तरीका बन गया है। एक एकल, अच्छी तरह से तैयार की गई छवि में भावनाओं, विचारों और आख्यानों को व्यक्त करने की शक्ति होती है जो शब्दों को एनकैप्सुलेट करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इस पर निर्माण, उदाहरण के लिए, शॉर्ट-फॉर्म वीडियो और 30-सेकंड रीलों का विस्फोट, परिदृश्य को और बदल दिया गया है। उनकी संक्षिप्तता और भावनात्मक गहराई उन्हें जनता की राय को आकार देने, समर्थन जुटाने और यहां तक कि तनाव को कम करने में अद्वितीय प्रभाव के उपकरण बनाती है। यह विकास भू -राजनीतिक क्षेत्र में संचारकों पर अपार जिम्मेदारी रखता है। कूटनीति, एक बार मुख्य रूप से बंद दरवाजों के पीछे आयोजित की जाती है, डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा प्रवर्धित क्यूरेटेड विजुअल, प्रतीकात्मक इशारों और रणनीतिक संदेश के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में तेजी से खेल रही है। विदेश नीति के लिए, चुनौती यह है कि संवेदनशीलता बनाए रखते हुए ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करते हुए, पारदर्शिता और रणनीति को संतुलित करना है। जैसा कि सोशल मीडिया ने अपनी तेजी से वृद्धि जारी रखी है, कई लोग पूछते हैं कि क्या पारंपरिक मीडिया अभी भी इस डिजिटल बाजीगरी के सामने अपनी जमीन पकड़ सकता है। सोशल मीडिया ने व्यक्तियों, सरकारों और संगठनों को अपने दर्शकों के लिए एक सीधा चैनल देते हुए, वैश्विक रूप से वैश्विक और लोकतांत्रिक संचार किया है। यह, सगाई और वायरल जाने की शक्ति पर पनपता है, जिससे यह भू -राजनीतिक संचार में एक आवश्यक उपकरण बन जाता है। हालांकि, पारंपरिक मीडिया अप्रचलित से दूर है। सूचना अधिभार के युग में, एक विश्वसनीय द्वारपाल के रूप में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जबकि सोशल मीडिया इस समय का दूत है, पारंपरिक मीडिया गहराई, विश्लेषण और संदर्भ प्रदान करता है- ऐसे तत्व जो सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। संचार के लिए इस नए भू -राजनीतिक युग में प्रभावी होने के लिए, दो माध्यमों को एक -दूसरे को पूरक करना चाहिए, एक समग्र कथा का निर्माण करना चाहिए जो तत्काल और स्थायी दोनों है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय ने वैश्विक संचार में जटिलता की एक और परत को जोड़ा है। एआई-चालित एनालिटिक्स दर्शकों के व्यवहार, वरीयताओं और भावनाओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि को सक्षम करते हैं, इसके लिए अनुमति देते हैंहाइपर-पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग। ये उपकरण राजनयिकों और विदेश नीति विशेषज्ञों के लिए अमूल्य हैं, जो अब अपार सटीकता के साथ संदेशों को शिल्प कर सकते हैं और अधिक सटीकता के साथ उनके प्रभाव की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि, इन प्रगति के साथ नैतिक दुविधाएं आती हैं। रणनीतिक संचार और हेरफेर के बीच की रेखा आसानी से धुंधला हो सकती है, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत ढांचे की आवश्यकता होती है। जैसे -जैसे संचार परिदृश्य अधिक जटिल हो जाता है, कुशल विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है। ये पेशेवर केवल सूचना के लिए चैनल नहीं हैं, वे रणनीतिकार, विश्लेषक और रचनाकार हैं जो विविध और तेजी से बदलती दुनिया में संदेश की बारीकियों को समझते हैं। पारंपरिक मीडिया को डिजिटल नवाचारों और दर्शकों-केंद्रित दृष्टिकोणों को गले लगाने के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए विकसित होना चाहिए। इस बीच, सोशल मीडिया को गलत सूचना, ध्रुवीकरण और गूंज कक्षों के मुद्दों से जूझना चाहिए, एक मंच बनने का प्रयास करना चाहिए जो विभाजित होने के बजाय एकजुट हो। इस युग में, संचार अब केवल एक संदेश देने के बारे में नहीं है; यह धारणाओं को आकार देने, संबंधों के निर्माण और ड्राइविंग कार्रवाई के बारे में है। जैसे-जैसे दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ती जाती है, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता नव-सामूहिक रूप से राजनीतिक युग की जटिलताओं को नेविगेट करने में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक होगी। गठबंधनों को स्थानांतरित करने और वैश्विक प्राथमिकताओं को विकसित करने से चिह्नित युग में, बहुपक्षीय संस्थानों को चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के लिए प्रतिबद्धताओं के पुनः काम ने वैश्विक सहमति की नाजुकता को नोटिस किया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसी साझा चुनौतियों को संबोधित करने में इन संस्थानों की भूमिका और प्रासंगिकता के बारे में सवाल उठाते हैं। यह स्थानांतरण परिदृश्य सामूहिक जिम्मेदारी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ बहुपक्षीय स्थानों के भीतर कूटनीति के लिए अधिक बारीक दृष्टिकोण के लिए कहता है। इन संस्थानों के लिए एक जटिल भू -राजनीतिक जलवायु में पनपने के लिए, उन्हें पारदर्शिता को बढ़ावा देने, विविध हितधारकों को संलग्न करने और कार्रवाई को चलाने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिए। चाहे एक कैमरे के लेंस के माध्यम से, एक ट्वीट की पहुंच, या एक खोजी रिपोर्ट की गहराई, हम जो कहानियां बताते हैं और हम उन्हें कैसे बताते हैं, वह दुनिया को उन तरीकों से आकार देगा जो हम केवल समझने लगे हैं।

बेलगाम होते जा रहे कोचिंग संस्थान

विजय गर्ग

हाल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों में से एक फिटजी के कई सेंटर बीच सत्र में ही अचानक बंद हो गए। इससे लाखों की संख्या में छात्रों की पढ़ाई तो अधर में लटकी ही, अभिभावकों का विश्वास और उनकी वित्तीय स्थिति भी हिल गई। फिटजी के प्रभावित होने वाले केंद्र दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, पटना आदि शहरों के हैं, जिनमें एक-एक सेंटर में छात्रों का आंकड़ा हजारों तक पहुंच रहा था। लगभग तीन लाख प्रति छात्र सालाना शुल्क वसूलने वाले इस कोचिंग संस्थान ने जेईई और नीट यूजी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के बीच अपनी एक खास छवि स्थापित कर ली थी, पर अभिभावकों के सपनों को पूरा करने और युवा भविष्य को तराशने का काम करने वाले इस संस्थान को अब संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। नोएडा पुलिस ने संस्थान के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बैंक खाते सीज कर दिए हैं। जांच के दौरान पुलिस को अलग-अलग बैंकों में फिटजी के सैकड़ों बैंक खाते मिले। कहा जा रहा है कि कई महीनों से वेतन न मिलने की स्थिति में हताश शिक्षकों द्वारा सामूहिक त्यागपत्र के कारण कई सेंटरों पर ताले पड़ गए। छात्रों और अभिभावकों के शोर मचाने पर अन्य केंद्रों से शिक्षकों को लाने के प्रयास किए गए, लेकिन वे नाकाम रहे। इस स्थिति में प्रशासन के पास कोचिंग सेंटरों का संचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। कोई ठोस कानून और नियमावली के अभाव में पुलिस एवं प्रशासन अभिभावकों को कोरी सांत्वना के आलावा कुछ भी नहीं दे पाया।

प्रतिष्ठित आइआइटी संस्थानों में प्रवेश की गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख के आसपास छात्र आवेदन करते हैं। इनमें से लगभग एक प्रतिशत ही आइआइटी में प्रवेश पा पाते हैं। यह एक अलग विषय है कि प्रतियोगी परीक्षा के दुर्गम होते स्तर से प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम प्रतिभा चयनित करने की पूर्ति हो रही हो या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि छात्रों एवं अभिभावकों की कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता बढ़ गई है। जैसी । प्रतिस्पर्धा जेईई को लेकर देखने को मिलती है, वैसी ही नीट - यूजी को लेकर भी । कठिन प्रतिस्पर्धा के चलते सतत मानसिक दबाव से जूझ रहे किशोरों में मानसिक अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसे बढ़ते विकार किसी से छिपे नहीं हैं। लुभावने वादों के सहारे कठिन प्रतिस्पर्धा को भुनाने वाले कोचिंग संस्थान आज शिक्षातंत्र में विद्यालयों को अप्रासंगिक कर स्वच्छंदता से पनप रहे हैं। इसकी पुष्टि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में गड़बड़ी के बाद गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से होती है । इस समिति ने कहा था कि कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली से संबंधित विशेष नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा एक समानांतर शैक्षणिक प्रणाली निर्मित कर ली गई है, जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की स्कूली शिक्षा के लिए घातक साबित हो रही है। इस समानांतर प्रणाली के कारण विद्यार्थियों की स्कूली उपस्थिति में भी कमी आई है। बीते दिनों शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने भी शिक्षा संस्थानों और कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ते गठजोड़ पर गहरी चिंता जताई और केंद्र सरकार से दोनों के नापाक गठजोड़ को खत्म करने की सिफारिश की। इस समिति ने इस पर भी जोर दिया कि कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर काम करने वाले शिक्षा संस्थानों की पहचान कर उनकी मान्यता रद की जाए और उन्हें मिलने वाली वित्तीय मदद रोकी जाए। आज कोचिंग संस्कृति की यह स्थिति है कि छात्र स्कूल जाएं या नहीं, परंतु कोचिंग उनकी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बन चुकी है।

2023 में फिटजी का राजस्व लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये दर्शाया गया था। देश में फिटजी जैसे अन्य कोचिंग संस्थान भी हैं, जो मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वे किसी संवैधानिक एजेंसी द्वारा विनियमित नहीं हैं। कोचिंग संस्थानों पर उपभोक्ता संरक्षण एवं वाणिज्यिक कानून भी प्रभावी रूप से लागू नहीं पा रहे हैं। नतीजन समय-समय पर छात्र ठगे जाते हैं। गत वर्ष दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान के जरिये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की उसके बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई थी। इसके पहले शैक्षिक स्टार्टअप बायजूस दिवालिया घोषित हो गया था। कोचिंग संस्थानों के मनमाने तरीके से संचालन से छात्रों को केवल वित्तीय हानि ही नहीं उठानी पड़ती, बल्कि उनके समय की भी बर्बादी होती है। छात्रों के साथ अभिभावकों के सपनों पर पानी भी फिरता है। ऐसे में कोचिंग संस्थाओं की मनमानी को महज आर्थिक हानि नहीं माना जाना चाहिए। इससे छात्रों के भविष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए कोचिंग संस्थानों के अनुचित कार्यों को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। इसके बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

छात्रों और अभिभावकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए कोचिंग संस्थाओं को किसी ठोस कानूनी नियमावली के दायरे में लाया जाना आवश्यक है। इस नियमावली में फीस, शैक्षिक गुणवत्ता के मानक, पाठ्यक्रम, स्टाफ का वेतन आदि महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होने चाहिए। गुरुओं के देश भारत के शैक्षिक तंत्र की वर्तमान चुनौतियों का सामना किए बिना समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षक एवं छात्रों के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

पत्नी की मुस्कान, सांसत में जान

विजय गर्ग

पत्नी जब मुस्कुराती है तो अच्छे-अच्छे पतियों को नानी याद आ जाती है। पति जानता है कि पत्नी वैसे ही खाली-पीली नहीं मुस्कुराती। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज़ होते हैं। पत्नी को मुस्कुराते देख कई पतियों का तो दिल बैठ जाता है। पत्नी जब मुस्कुराती है तो अक्सर दो बातों की संभावना होती है। या तो पति की जेब पर डाका पड़ने वाला है या पति का कोई राज़ पत्नी को मालूम चल गया है। दोनों ही स्थितियों में पति की शामत ही समझो। एक दुस्साहसी पति ने अपनी मुस्कुराती पत्नी से इसका कारण पूछा तो पत्नी बोली, 'अब क्या मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती। आप तो जब-तब अट्टहास करते रहते हो। मेरे मुस्कुराने पर भी बैन लगाओगे?'

'अरे भई मैं तो सिर्फ मुस्कुराने का कारण पूछ रहा हूं। कोई तो वजह होगी या यूं ही...।'

'तो मैं यूं ही मुस्कुरा नहीं सकती? जरूरी है क्या मुस्कुराने के पीछे कोई वजह हो।' पत्नी के तेवर बदल चुके थे। वह मुस्कुराहट से सीधे डांट-डपट वाले भाव में आ गई थी। 'नाराज क्यों हो रही हो, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था।' पति डरते-सहमते बोला।

'जब मेरे मुस्कुराने पर तुम्हें आपत्ति है तो मेरे हंसने पर क्या करोगे। वैसे भी तुमसे शादी के बाद तो मैं हंसना-मुस्कुराना ही भूल गई हूं। मुझे याद है पिछली बार मायके गई थी, वहां हंसना-हंसाना हुआ था। हर समय रोनी सूरत बनाए रखते हो, तुम्हारे चढ़े हुए थोबड़े को देखकर भला कौन मुस्कुरा सकता है।' पत्नी के मुंह से दे-दनादन क्रांतिकारी शब्दों का उत्पादन होने लगा था। पति को महसूस हो गया था कि उसने पत्नी से उसकी मुस्कान के बारे में पूछकर बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया है।

'चलो जाने दो...। यह बताओ आज खाने में क्या बनाया है।' पति ने विषय बदलते हुए कहा।

'बदल दी न बात। तुम से कुछ कहो तो झट बात बदल लेते हो। इसीलिए तो मेरी मुस्कान चली गई है। थोड़ी भी हंसने-मुस्कुराने की वजह आई नहीं कि पूछताछ करने लगते हो। अब इंसान क्या किसी वजह से ही हंसे-मुस्कुराए? बिना बात भी तो मुस्कुरा सकता है। तुम्हारा तो एक ही काम है। जब देखो तब यही पूछते रहते हो कि आज खाने में क्या बनाया है...। जो बन जाए खा लेना। मैं कौन से छप्पन भोग खाऊंगी, वही खाऊंगी जो तुम्हारे लिए बनेगा। जब भी हंसती-मुस्कुराती हूं, पूछने लगते हो खाने में क्या बनाया है। आदमी क्या खाने के लिए ही जी रहा है?' पति को काटो तो खून नहीं।

'मैंने तो बस तुम्हारे मुस्कुराने की वजह ही तो पूछी थी, कौन-सा गुनाह कर दिया।' पति अब झल्लाने लगा था।

'तो मैंने ऐसा क्या कह दिया, जो तुम इतना झींक रहे हो। बात ही तो कर रही हूं। अब कुछ कह-सुन भी नहीं सकती क्या...।' पत्नी टप-टप आंसू गिराने लगी थी। पति हतप्रभ था। क्या करता। पत्नी को मनाने में लग गया।

लैपटॉप और मोबाइल से कौन सी रोशनी निकलती हैं कितनी है खतरनाक, समझें इसके पीछे का साइंस

विजय गर्ग

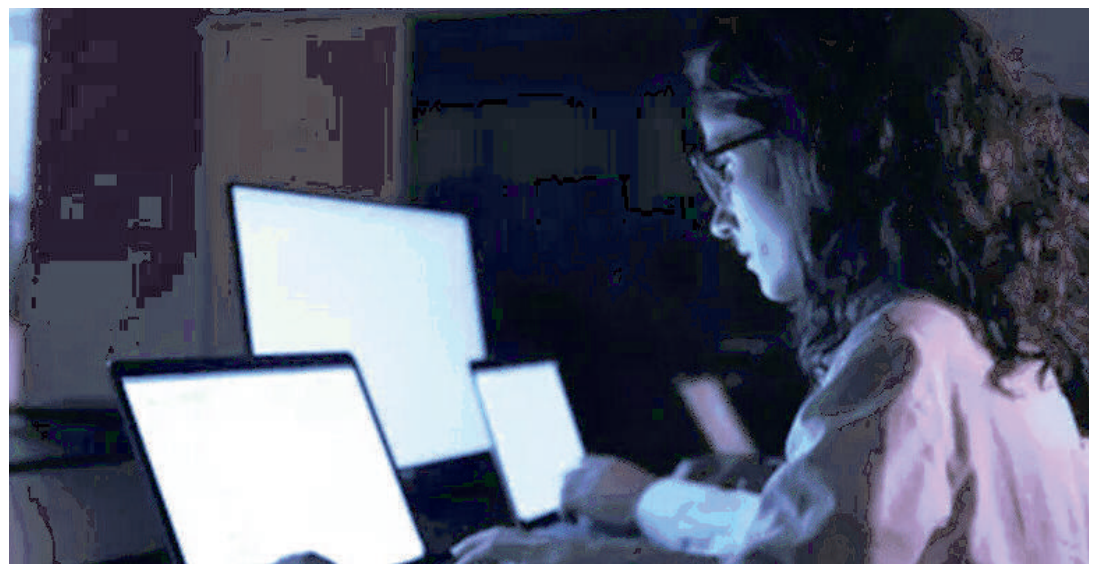

आज के डिजिटल युग में हम लगातार स्क्रीन से घिरे रहते हैं जिसकी रोशनी हमारी आंखों के साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है. इनसे निकलने वाली रोशनी उम्र बढ़ने, सूजन और टिशू को नुकसान पहुंचाने का भी कारण बनती है. आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहता है साइंस. हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हमें टीवी स्क्रीन, मोबाइल फोन और लैपटॉप के सामने ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए. अक्सर हमें घर में अपने माता-पिता से इस बात के लिए डांट भी पड़ती है कि इससे हमारी आंखें खराब हो जाएंगी. हालांकि, हम हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है. हालांकि, विज्ञान की दृष्टि से यह सच है कि लंबे समय तक स्क्रीन से घिरे रहने से इनसे निकलने वाली नीली रोशनी के कारण आंखों के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है. आज के डिजिटल युग में हम लगातार ऐसी स्क्रीन से घिरे रहते हैं जिनसे नीली रोशनी निकलती है जो कई तरह से हानिकारक हो सकती है. इस लेख में आगे जानते हैं कि आखिर क्या है यह नीली रोशनी. हमारे स्वास्थ्य को यह किस तरह प्रभावित करती है.

नीली रोशनी यानी हाई इंटेंसिटी विजिबल लाइट

डिजिटल डिवाइस यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी को हाई इंटेंसिटी विजिबल लाइट (HEV) कहते हैं. हिंदी में इसका मतलब है हाई-एनर्जी विजिबल लाइट. नीली रोशनी की वेवलेंथ कम होती है जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती है. यह एक ऐसा हल्का रंग है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं. लैपटॉप समेत कई डिजिटल डिवाइस से यह निकलती है. नीली रोशनी के कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता . नीली रोशनी सूर्य के प्रकाश में भी मौजूद होती है.

अमेरिका की एक सरकारी संस्था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के शोध के मुताबिक नीली रोशनी की वेवलेंथ 400-500 एनएम होती है और यह विजिबल लाइट का करीब एक तिहाई होती है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आर्टिफिशियल इनडोर लाइटिंग से भी नीली रोशनी निकलती है. अध्ययनों से पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली रोशनी के संपर्क में आने से, चाहे वह 1 घंटे के लिए ही क्यों न हो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस बढ़ सकता है. और इसके कारण आंखों में कई तरह की परेशानी हो सकती है.

आंखों में तनाव, सिरदर्द और उम्र का खतरा

रिसर्च में बताया गया है कि नीली रोशनी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हमारी आंखों के स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं. सबसे आम मुद्दों में से एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का विकास है. सीवीएस का मतलब है आंखों और दृष्टि से जुड़ी समस्याओं का एक समूह जो लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने के कारण होता है. इसके लक्षणों में आंखों में तनाव, धुंधली दृष्टि, सूखी आंखें, सिरदर्द और गर्दन और कंधे में दर्द शामिल हैं. नीली रोशनी आंखों की थकान का भी कारण बन सकती है जिससे यह कंट्रास्ट को कम कर देती है. इसके बाद आंखों के लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है.

वहीं, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि नीली रोशनी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से समय के साथ रेटिना को नुकसान हो सकता है. साथ कहा जाता है कि इससे मैकुलर डिजनरेशन का भी जोखिम बढ़ जाता है. माना जाता है कि नीली रोशनी के लगातार संपर्क में रहने से उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन का जोखिम बढ़ सकता है, जो उम्रदराज लोगों में दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है. रिसर्च में पाया गया है कि नीली रोशनी के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने, सूजन और टिशू क्षति से जुड़े प्रोटीन बायोमार्कर में काफी बढ़ोतरी होती है. नीली रोशनी के प्रभावों से बचने के उपाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि लगातार नीली रोशनी के संपर्क में रहने से त्वचा की उम्र बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. यह त्वचा में शामिल बायोलॉजिकल रूट्स को बदलकर त्वचा को नुकसान पहुंचाता है. लगातार 5 दिनों तक 6 घंटे तक नीली रोशनी के संपर्क में रहने से सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव मार्गों को नियंत्रित करने वाले जीन का प्रदर्शन बढ़ जाता है. यह त्वचा की बाधा और टिशू को समान्य बनाए रखने वाले जीन के प्रदर्शन को भी कम करता है.

नीली रोशनी के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए, घर में एलईडी और फ्लोरोसेंट लाइटिंग को कम करने की सलाह दी जा सकती है. विशेष रूप से, स्क्रीन देखने में बिताए जाने वाले समय को सीमित करें. इससे बचने के लिए, पीले लेंस वाले कंप्यूटर चश्मे का भी उपयोग किया जाता है. ये चश्मे कंट्रास्ट बढ़ाते हैं और नीली रोशनी को रोकते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है और उनके सुझाव के अनुसार है. यदि आपको आंखों में खिंचाव या इससे संबंधित कोई समस्या महसूस होती है, तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से परामर्श करना उचित है.

2 साल के इंतजार के बाद ज्वाइनिंग, 6 महीने बाद ही छंटनी; सैकड़ों ट्रेनी बेरोजगार

परिवहन विशेष न्यूज

इन्फोसिस ने करीब दो साल पहले सैकड़ों आईटी ग्रेजुएट को जॉब ऑफर की थी। लेकिन बिजनेस से जुड़ी चुनौतियों के चलते उन्हें सितंबर में ज्वाइनिंग कराई। लेकिन इन्फोसिस में नौकरी के लिए दो साल का इंतजार करने वाले आईटी ग्रेजुएट को उस वक्त बड़ा सदमा लगा जब सिर्फ 6 महीने बाद उनकी सामूहिक छंटनी कर दी गई। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।

नई दिल्ली। आईटी कर्मचारियों की यूनियन नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लॉइज सीनेट (NITES) ने शुक्रवार को दावा किया कि आईटी दिग्गज इन्फोसिस ने अपने मैसूर कैंपस से करीब 700 फ्रेशर्स को नौकरी से निकाल दिया है। यूनियन के मुताबिक, फ्रेशर्स को कंपनी में आने के कुछ ही महीनों बाद छंटनी का शिकार होना पड़ा है।

इन्फोसिस के फाउंडर एन नारायण मूर्ति अक्सर अपने वर्क कल्चर से जुड़े बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वह हफ्ते में 70 घंटे काम करने की वकालत करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स इन्फोसिस में ट्रेनियों की बड़े पैमाने पर छंटनी होने पर नाराजगी जता रहे हैं। वे इन्फोसिस और उसके मैनेजमेंट की तीखी आलोचना भी कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

इन्फोसिस ने करीब दो साल पहले सैकड़ों आईटी ग्रेजुएट को जॉब ऑफर की थी। लेकिन, बिजनेस से जुड़ी चुनौतियों के चलते उन्हें सितंबर में ज्वाइनिंग कराई। लेकिन, इन्फोसिस में नौकरी के लिए दो साल का इंतजार करने वाले आईटी ग्रेजुएट को उस वक्त बड़ा सदमा लगा, जब सिर्फ 6 महीने बाद उनकी सामूहिक छंटनी कर दी गई।

ये ट्रेनी जब घर लौटने के लिए टैक्सी और बस बुक करने पहुंचे, तो उनके सामने बड़ा सवाल यही था कि वे अपने परिवारों को यह खबर कैसे बताएंगे?

कर्मचारियों के डराने के लिए बाउंसर?

NITES के चेयरपर्सन हरप्रीत सिंह सलूजा ने एक बयान में कहा, ₹इन्फोसिस ने करीब 700 कैंपस हायरिंग को जबरन नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। उन लोगों को कुछ महीने पहले कंपनी में जगह मिली थी। यह बेहद हैरान करने वाली अनैतिक कदम है।'

NITES का आरोप है कि कंपनी ने बर्खास्तगी प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को डराने के लिए ₹बाउंसर और सुरक्षा कर्मियों₹ को भी तैनात किया था।

सोशल मीडिया पर आक्रोश

इन्फोसिस में फ्रेशर्स की बड़े पैमाने पर छंटनी होने से सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। कई लोगों ने प्रभावित कर्मचारियों से सहानुभूति जताई और कंपनी के फैसले की आलोचना की।

एक यूजर ने अपने एक्स पर लिखा, ₹यह वास्तव में दिल तोड़ने वाला है। इन फ्रेशर्स ने इन्फोसिस से ऑफर लेटर मिलने के बाद 2-2.5 साल इंतजार किया। आखिरकार सितंबर 2024 में उनकी ज्वाइनिंग हुई। अब सिर्फ छह महीने बाद उनमें से लगभग 700 को नौकरी से निकाल दिया गया है। कई फ्रेशर्स ने 2 साल के दरम्यान कई अन्य मौकों को ठुकरा दिया होगा कि उन्हें इन्फोसिस में काम करने का मौका मिलेगा। अब उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है।'

इन्फोसिस ने क्या प्रतिक्रिया दी?

इन्फोसिस का कहना है कि कंपनी में हायरिंग प्रोसेस काफी सख्त है। मैसूर कैंपस में शुरुआती ट्रेनिंग लेने के बाद सभी फ्रेशर्स को इंटरनल टेस्ट पास करना था। इसके लिए फ्रेशर्स को टेस्ट पास करने के लिए तीन मौके मिलते हैं, जिसमें फेल होने वालों को कंपनी में नहीं रखा जाता। कंपनी ने जोर देकर कहा कि यह शर्त कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी है।

हालांकि, फ्रेशर्स का दावा है कि उन्हें फेल करने के लिए जानबूझकर सख्त टेस्ट बनाए गए थे। इन्फोसिस ने इस बात से इनकार किया है कि कर्मचारियों को डराने के लिए बाउंसर तैनात किए गए थे।

महंगाई से मिली बड़ी राहत, क्या अब शेयर बाजार में आएगी तेजी?

परिवहन विशेष न्यूज

महंगाई के आंकड़ों पर शेयर बाजार के निवेशकों की भी बारीक नजर थी। पिछले कई कारोबारी सत्रों से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अब महंगाई घटने से बाजार में तेजी वापस लौट सकती है। क्योंकि इससे आरबीआई के लिए आगामी MPC मीटिंग में रेट कट करने के रास्ते खुल जाएंगे। आरबीआई ने फरवरी MPC में ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की है।

नई दिल्ली। आम जनता को एक के एक बड़ी राहत मिलती जा रही है। पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। फिर बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया। अब महंगाई दर कम होने से भी जनता को एक और राहत मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.31 फीसदी पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में 5.22 फीसदी और जनवरी 2024 में 5.1 फीसदी थी।

फूड बास्केट में मुद्रास्फीति 6.02 फीसदी रही, जो दिसंबर 2024 में 8.39 फीसदी थी। यह एक साल पहले जनवरी में 8.3 फीसदी थी। सरकार ने आरबीआई से यह तय करने को कहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति 2 फीसदी के घट-बढ़ के साथ 4 फीसदी पर बनी रहे। ऐसे में महंगाई दर घटकर 4.31 फीसदी पर आने से सरकार और आरबीआई को बड़ी मिली है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है।

महंगाई घटने से शेयर बाजार में आएगी?

महंगाई के आंकड़ों पर शेयर बाजार के निवेशकों की भी बारीक नजर थी। पिछले कई कारोबारी सत्रों से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन, अब महंगाई घटने का डेटा आने से बाजार में तेजी वापस लौट सकती है। क्योंकि इससे आरबीआई के लिए आगामी MPC मीटिंग में रेट कट करने के रास्ते खुल जाएंगे। आरबीआई ने फरवरी की MPC में ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की है।

अब अगर जनवरी के बाद फरवरी में भी महंगाई काबू में रहती है, तो अप्रैल की MPC में आरबीआई फिर से रेपो रेट कट पर विचार कर सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक, आरबीआई साल 2025 में ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की कटौती कर सकती है। इससे आम जनता के लिए होम लोन और कार लोन की लागत घट जाएगी। साथ ही, शेयर मार्केट को भी भारी बूस्ट मिलेगा।

बजट 2025 में मिली छूट के बाद कितना बचेगा टैक्स, बताएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया कैलकुलेटर

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार लगातार नए टैक्स सिस्टम को बढ़ावा दे रही है और बजट 2025 में इसे और आकर्षक बना दिया गया है। अगर आप ज्यादा टैक्स सेविंग चाहते हैं और ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं तो नया टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे खास बात कि इसमें आपको टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग योजनाओं निवेश करने की जरूरत नहीं रहेगी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया। हालांकि, अभी भी कई टैक्सपेयर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि बजट 2025 में हुए बदलाव के बाद उन्हें कितना टैक्स कम देना पड़ेगा। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने नई इनकम टैक्स कैलकुलेटर सुविधा शुरू की है। इससे तुलना करके पता किया जा सकता है कि किसी खास इनकम पर बजट से पहले कितना टैक्स देना पड़ता था और नए वित्त वर्ष से कितना टैक्स देना होगा।

अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अपनी टैक्स सेविंग की सही प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आयकर विभाग (Income Tax Department) के इस कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी संभावित टैक्स बचत को कैलकुलेट कर सकते हैं।

बजट 2025 में क्या बदलाव हुए हैं?

बजट 2025 के अनुसार, अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई टैक्स दरें (New Tax Slabs) पहले के मुकाबले कम कर दी गई हैं, जिससे टैक्स का बोझ कम होगा।

सरकार ने नए टैक्स रेजीम को और आकर्षक बनाने के लिए टैक्स छूट (Tax Rebate) को बढ़ाया है।

कैसे करें इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग?

अगर आप जानना चाहते हैं कि बजट 2025 में घोषित नई टैक्स स्लैब्स के अनुसार आपको कितनी टैक्स छूट मिलेगी, तो आप इस कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

₹इनकम टैक्स कैलकुलेटर₹ सेक्शन को चुनें।

अपना Residential Status दर्ज करें।

अपनी कुल Taxable Income दर्ज करें (स्पेशल रेट वाली इनकम जैसे कैपिटल गेन को छोड़कर)।

कैलकुलेटर पुराने और नई व्यवस्था के हिसाब से आपकी टैक्स देनदारी की तुलना करेगा।

यह दिखाएगा कि टैक्स पर अब आपको कितनी बचत हो रही है।

बजट 2025 के बाद नया टैक्स स्लैब

सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया है। अब 12 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट की लिमिट 7 लाख रुपये थी। आइए जानते हैं प्रस्तावित टैक्स दर।

4 लाख रुपये तक - 0% टैक्स
4-8 लाख रुपये - 5% टैक्स
8 12 लाख रुपये - 10% टैक्स
12-16 लाख रुपये - 15% टैक्स
16-20 लाख रुपये - 20% टैक्स
20-24 लाख रुपये - 25% टैक्स
24 लाख रुपये से अधिक - 30% टैक्स

नए टैक्स रिजीम की खास बातें

अब नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगा, यानी पुराना टैक्स सिस्टम चुने के लिए आवेदन करना होगा।

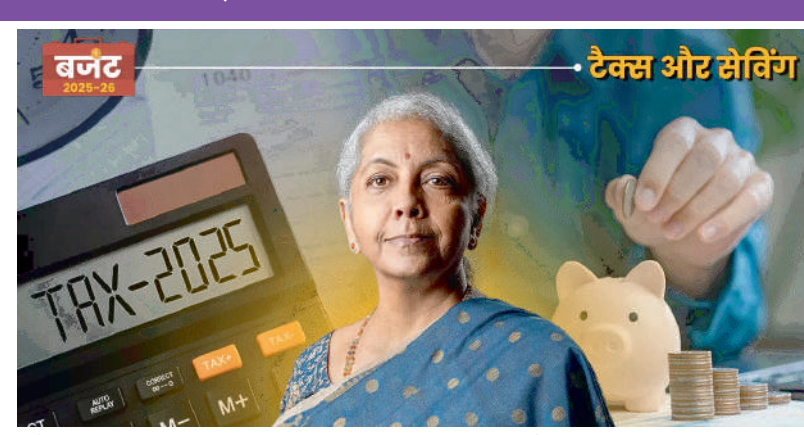

बेसिक छूट (Exemption Limit) बढ़ाई गई। पहले यह ₹3 लाख थी, जो अब ₹4 लाख कर दी गई है।

टैक्स छूट (Rebate) की लिमिट भी बढ़ी। अब 7 लाख के बजाय 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी।

सेक्शन 87A के तहत 25,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती थी, जिसे अब 60,000 कर रुपये कर दिया गया है।

इसमें पुराने टैक्स रिजीम की तरह ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा डिडक्शन का लाभ जारी रहेगा।

नए टैक्स रेजीम में मिलने वाली डिडक्शन

हालांकि नया टैक्स सिस्टम पुरानी व्यवस्था के मुकाबले कम डिडक्शन देता है। हालांकि, कुछ डिडक्शन अभी भी उपलब्ध हैं।

सैलरीड टैक्सपेयर्स (Salaried Taxpayers) को 75,000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) का लाभ मिलेगा।

एनपीएस (NPS) में इम्प्लॉयर का अंशान (Employer Contribution to NPS) पर टैक्स छूट रहेगी। इसमें बेसिक सैलरी का 14% तक डिडक्शन मिलेगा।

क्या नया टैक्स रिजीम आपके लिए सही है?

सरकार लगातार नए टैक्स सिस्टम को बढ़ावा दे रही है और बजट 2025 में इसे और आकर्षक बना दिया गया है। अगर आप ज्यादा टैक्स सेविंग चाहते हैं और ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, तो नया टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे खास बात कि इसमें आपको टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग योजनाओं निवेश करने की जरूरत नहीं रहेगी।

'सरकारी योजनाओं की वजह से काम नहीं करना चाहते लेबर', ये क्या बोल गए L&T के चेयरमैन

परिवहन विशेष न्यूज

लार्सन एंड टुब्रो (LT) के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन का कहना है कि भारत में लोग मनरेगा और डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी स्कीमों के चलते दूसरे शहरों में जाकर काम नहीं करना चाहते। उन्होंने मजदूरों की तनख्वाह को महंगाई के अनुसार बढ़ाने की जरूरत भी बताई। क्योंकि मध्य पूर्व में भारत की तुलना में 3 से 3.5 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है जिससे वे वहां काम करने चले जाते हैं।

नई दिल्ली। लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं की भरमार के चलते श्रमिक दूसरे शहरों में जाकर काम नहीं करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को एक हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। उसके बाद वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस शुरू हो गई थी।

सुब्रमण्यन ने मंगलवार को चेन्नई में सीआईआई के मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 में बोलते हुए कहा कि निर्माण उद्योग के लिए श्रमिक मिलना मुश्किल है क्योंकि वे आराम की वजह से अपना गृहनगर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि मनरेगा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर और जन धन खातों जैसी योजनाओं से श्रमिक जुटाने पर असर पड़ सकता है।

मजदूरी बढ़ाने की भी वकालत की

सुब्रमण्यन ने कहा, ₹श्रमिक नए अवसर की तलाश में आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं है। हो सकता है कि स्थानीय कमाई से उनका काम अच्छे से चल रहा हो। या फिर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते दूसरे शहर में जाकर काम करने की जरूरत न हो।' उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कमी से भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर असर पड़ेगा।

सुब्रह्मण्यन ने कहा कि भारत में प्रवास (Migration) की अनोखी समस्या है। एलएंडटी (L&T) को 4 लाख मजदूरों की जरूरत होती है, लेकिन बार-बार लोग नौकरी छोड़ते हैं, इसलिए उन्हें 16 लाख लोगों को भर्ती करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों की तनख्वाह को महंगाई के अनुसार बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मध्य पूर्व (Middle East) देशों में मजदूरों को भारत की तुलना में 3 से 3.5 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है, जिससे वे वहां काम करने चले जाते हैं।

वर्क-लाइफ बैलेंस पर क्या कहा था?

लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन ने पिछले महीने कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके कर्मचारी रविवार को भी काम करें। उन्होंने कहा था, ₹आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? चलिए, ऑफिस जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए।₹ उन्होंने यह भी कहा था कि वह रविवार को भी काम करते हैं।

इस बहस में अदार पूनावाला, आनंद महिंद्रा और आईटीसी के संजीव पुरी जैसे दिग्गज उद्योगपति भी उतर गए थे। उन्होंने उत्पादकता के लिए वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत की वकालत की। यह मामला संसद तक भी पहुंचा। सरकार ने पिछले सप्ताह संसद को बताया कि वह अधिकतम कार्य घंटों को बढ़ाकर 70 या 90 घंटे प्रति सप्ताह करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

सप्ताह में 70-90 घंटे काम करने के बारे में चर्चा के दौरान, पिछले शुक्रवार को बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया था कि एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

सर्वे में पाया गया कि अपने डेस्क पर लंबे समय तक बैठना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति अपने डेस्क पर (प्रतिदिन) 12 या इससे अधिक घंटे बिताते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की आशंका अधिक रहती है।

लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, पर चांदी की कीमतों में तेजी; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 340 रुपये की गिरावट के साथ 87,960 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मंगलवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला कीमती धातु 88,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 340 रुपये की गिरावट के साथ 87,560 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 87,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, बुधवार को चांदी की कीमत 600 रुपये बढ़कर 97,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इस बीच, एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 659 रुपये या 0.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,864 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई।

सोने की कीमत बढ़ने पर एक्सपर्ट की राय

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी ने कहा, ₹कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों में कीमतों में कमजोरी के साथ सोने ने अपनी मजबूत तेजी के बाद राहत की सांस ली। एमसीएक्स पर सोने में गिरावट कुछ दबाव का संकेत देती है।₹ उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े ब्याज दर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे, जो सोने की चाल को प्रभावित कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कॉमेक्स सोना वायदा 26 डॉलर प्रति औंस गिरकर 2,906.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ₹बुधवार को सोने में गिरावट आई, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने बताया कि ब्याज दरों में और कटौती की कोई तत्काल जरूरत नहीं है। इससे ब्याज दरों में आक्रामक कटौती की उम्मीदें कम हुई हैं।'

क्यों बढ़ रही सोने की चमक, क्या 1 लाख रुपये के पार पहुंच जाएगा भाव?

परिवहन विशेष न्यूज

सोने की कीमत में उछाल अभी सोने का भाव 86360 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसका मतलब है कि सोने को 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने के लिए 14000 रुपये यानी लगभग 16 फीसदी और बढ़ना होगा। आइए जानते हैं कि क्या सोने की कीमतों में आगे भी तेजी जारी रहेगी। क्या साल 2025 में सोने के भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच जाएगी।

नई दिल्ली। पिछले साल सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। यह साल 2025 में भी जारी है। इस साल करीब डेढ़ महीने में ही सोने की कीमतों में 8,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (लगभग 11 फीसदी) की बढ़ोतरी हो चुकी है। हाल ही में सोना 86,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। अब सवाल उठता है कि सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है और क्या सोना आने वाले महीनों में 1 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है?

सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों से लगातार ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ रहा है।

भारत में शादी का सीजन चल रहा है। इस दौरान सोने की खरीदारी से डिमांड और प्राइस में तेजी आ रही है।

डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। इसका असर भी सोने की कीमतों में देखने को मिल रहा है।

वैश्विक बाजार में महंगाई दर अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसलिए लोग सोने में निवेश कर रहे हैं।

शेयर मार्केट में भारी गिरावट के चलते निवेशकों का रुझान सोने की तरफ तेजी से बढ़ रही है।

क्या 1 लाख के पार जाएगा सोना?

अभी सोने का भाव 86,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसका मतलब है कि सोने को 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने के लिए 14,000 रुपये यानी लगभग 16 फीसदी और बढ़ना होगा। हालांकि, अधिकांश एक्सपर्ट का मानना है कि सोने में तेजी जारी रह सकती है, लेकिन 2025 में सोने का 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छूना मुश्किल होगा।

आनंद राठी शेयर ब्रोकर्स के डायरेक्टर नवीन माथुर के अनुसार, 2024 में सोना 27 फीसदी बढ़ा था। 2025 में अब तक 11 फीसदी बढ़ चुका है। इसकी प्रमुख वजह भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और ब्याज दर कटौती की उम्मीदों के कारण हुई है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोना दिवाली तक का 87,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। लेकिन, 1 लाख रुपये का स्तर फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा। कुछ अन्य एक्सपर्ट का मानना है कि सोने की कीमतें जल्द 90 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच सकती हैं।

क्या टैरिफ वॉर से सोने में और तेजी आएगी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका पैदा हो गई है। इस कारण निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश (Safe-Haven Asset) जैसे कि सोने की ओर बढ़ रहा है।

आर्थिक जानकारों का मानना है कि अगर टैरिफ विवाद और बढ़ता है, तो यह सोने की कीमतों को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है, तो सोने की कीमतों में गिरावट भी आ सकती है। की तेजी को सीमित कर सकता है।

विश्व रेडियो दिवस विशेष आलेख 13 फरवरी विशेष

आज का युग सूचना क्रांति का युग है, एडवांस एआई तकनीक का युग है। विज्ञान ने आज इतनी अधिक तरक्की कर ली है कि सूचना क्रांति और एआई तकनीक के इस आधुनिक युग में आज हमारे पास मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं।प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन आखेट, कथा-कहानी, आपबीती, तैराकी, घुड़सवारी, पर्यटन, चौसर, खेल-तमाशे, कुश्ती, कबड्डी,ताश, शतरंज ,कला, प्रदर्शन, नृत्य, संगीत, बाजे,नाटक, मेले, सामाजिक सभाएं(चौपाल),ढ़ोलक, हारमोनियम पर गाना आदि हुआ करते थे और मनुष्य इन साधनों के द्वारा मनोरंजन किया करता था। पहले के जमाने में आज की तरह न इंटरनेट की उपलब्धता ही थी और न ही स्मार्ट फ़ोन,लैपटॉप, टीवी ही हुआ करता था। कहना ग़लत नहीं होगा कि पहले के जमाने में मनोरंजन के सीमित संसाधन थे। वैसे पुराने जमाने में मनोरंजन का एक बड़ा साधन जो रहा है, वह 'रेडियो' है। कहना ग़लत नहीं होगा कि रेडियो जानकारी प्रदान करने, लोगों को शिक्षित करने, संस्कृतियों के बीच अभिव्यक्ति की अनुमति देने और निश्चित रूप से, हमारे सभी पसंदीदा संगीत बजाने का एक शानदार और सशक्त मंच है। चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, रेडियो एक अपूरणीय माध्यम है, खासकर प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान। सच तो यह है कि रेडियो आज प्रसारण का वह माध्यम है जो मनोरंजन, स्थानीय समाचार, खेल अपडेट, चर्चाएँ, बढ़िया संगीत प्रदान करता है, और मार्केटिंग का भी एक प्रभावी तरीका है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस आधुनिक युग में भी रेडियो की प्रासांगिकता समय के साथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और आज 13 फरवरी है- 'विश्व रेडियो दिवस।' पाठकों को बताता चलूं कि पहला रेडियो प्रसारण 1895 में गुग्लिल्मो मार्कोनी द्वारा किया गया था और संगीत और बातचीत का रेडियो प्रसारण, जिसका उद्देश्य व्यापक दर्शकों के लिए था, प्रयोगात्मक रूप से, कभी-कभी 1905-1906 के आसपास अस्तित्व में आया। यह भी उल्लेखनीय है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सबसे पहले रेडियो की संभावना का प्रस्ताव रखा था।साल 1920 के दशक की शुरुआत में रेडियो व्यावसायिक रूप से अस्तित्व में आया और लगभग तीन दशक बाद रेडियो स्टेशन अस्तित्व में आए और 1950 के दशक तक रेडियो और प्रसारण प्रणाली दुनिया भर में एक आम वस्तु बन गई। वास्तव में विश्व रेडियो दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच अधिक जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का उद्देश्य रेडियो स्टेशनों को अपने माध्यम से सूचना तक पहुंच प्रदान करने और प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। बहरहाल,भले ही आज के युग के बारे में कोई ये समझे कि आज का मल्टीप्लेक्स सिनेमा का युग है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का युग है। लेकिन रेडियो का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। शहरों में सिटी बसें दौड़ रहीं हों या आटो-टैक्सियां आपको इनमें रेडियो बजता हुआ सुन जाएगा। आज स्थान स्थान पर बहुत से कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स खुल गये हैं अथवा एफ.एम. की बहार है। सिटी बसेज में तो एफ.एम. का अपना अलग ही आनंद है। आप दिल्ली चले जाइए, जयपुर घूम आइए या किसी अन्य बड़े शहर की सैर कर आइए, आपको रेडियो मिर्ची, समाचार जरूर ट्यून होते मिलेंगे। चाय की थड़ियों में, दुकानों में अखबार पढ़ने के साथ ही आपको रेडियो सुनने का आनंद लेते लोग मिल जाएंगे। आज भागमभाग भरी व दौड़-धूप भरी इस जिंदगी में भी रेडियो की एक अपनी अलग ही महत्ता व खूबी है। गांवों में आज भी बहुत से लोग बड़े चाव से रेडियो सुनते हैं, क्योंकि रेडियो अनपढ़ और पढ़े-लिखे दोनों ही लोगों का परम्मित्र है। रेडियो वह शक्तिशाली माध्यम है जो लोकतान्त्रिक विमर्श के लिए एक शानदार मंच का निर्माण करता है। रेडियो संचार का सबसे अच्छा व बेहतरीन माध्यम है। वास्तव में रेडियो एक ऐसी सेवा है जो दुनियाभर में सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। यह बात सत्य है कि आज के समय में अधिकतर लोगों के लिए रेडियो पुराने जमाने की बात हो गई है, परंतु रेडियो बुजुर्गों के लिए आज भी मनोरंजन का एक अत्यंत सशक्त साधन व शानदार माध्यम है। मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग से अन्य वर्गों का इससे रुझान पहले से काफी कम हुआ है। लेकिन आज भी रेडियो पर हम सभी समाचार सुनतें हैं, कृषि संबंधी विभिन्न जानकारियां सुनते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में सुनते हैं, रेडियो फोन- इन -प्रोग्राम सुनते हैं, यहाँ तक कि नाटक,कहानी,वार्ता व विज्ञापन तक सुनते हैं। महानगरों में सिटी बसों में रेडियो ही बजता सुनाई देता है और इससे सवारियों का अच्छा खासा मनोरंजन होता है। वास्तव में सूचनाओं को आदान प्रदान करने में रेडियो की जो भूमिका है, वह किसी अन्य साधन की अब तक नहीं है, क्योंकि रेडियो सूचनाओं का प्रसार करने का सबसे शक्तिशाली और सस्ता माध्यम है। वैसे विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी।साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव दिया था। साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की। बाद में साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे अपना लिया। फिर उसी साल 13 फरवरी को पहली बार यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस मनाया। गौरतलब है कि इटली के पीसा विश्वविद्यालय में प्रथम विश्व रेडियो दिवस के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।पहली बार 13 फरवरी, 2012 को विश्व रेडियो दिवस आयोजन में विश्व की प्रमुख प्रसारक कंपनियों को बुलाया गया था जिसमें 44 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एवं पुरानी कंपनी रेडियो रूस भी शामिल हुई थी। भारत में 1936 में 'इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया' की शुरुआत हुई थी जो आजादी के बाद 'ऑल इंडिया रेडियो' के नाम से विख्यात हुआ। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर 'आकाशवाणी' कर दिया गया। 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के अपने ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी 27 भाषाओं में शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, खेलकूद, युवा, बाल एवं महिला तथा कृषि एवं पर्यावरण संबंधी प्रस्तुतियों से संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोते हुए सुवासित परिवेश निर्मित कर रही है। साथ ही शेष विश्व को भारतीय संस्कृति और साहित्य से परिचित भी करा रही है। 2 अक्टूबर, 1957 को स्थापित 'विविध भारती' ने 1967 से व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू कर नए युग में प्रवेश किया। यह भी बताना बड़ा रूचिकर होगा कि आजादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और आज बहुत से रेडियो स्टेशन उपलब्ध हैं। बताता चलूं कि हर साल रेडियो दिवस पर एक खास थीम तैयार की जाती है और इस साल यानी कि वर्ष 2022 की थीम 'विकास' थी। विश्व रेडियो दिवस 2023 का विषय 'रेडियो और शांति' रखा गया था। वहीं पर वर्ष 2024 में इसकी थीम 'रेडियोः सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी' रखी गई थी। पाठकों को बताता चलूं कि इस वर्ष यानी कि 2025 में रेडियो दिवस की थीम 'रेडियो और जलवायु परिवर्तन' रखी गई है।हमें यह भी जानना चाहिए कि डॉयचै वैले जर्मन अंतरराष्ट्रीय प्रसारणकर्ता है जो तीस भाषाओं में प्रसारण करता है। इसके अलावा वॉइस आफ अमेरिका, बीबीसी अन्य प्रमुख प्रसारणकर्ता हैं। एक दौर था जब देश में टेलीविजन नहीं हुआ करते थे और उस जमाने में हर कोई रेडियो सुनना पसंद करता था। आज तो टीवी है, टीवी भी नहीं एल ई डी टीवी आ गए हैं, स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्टफोन ही नहीं स्मार्ट घड़ियां भी आ चुकीं हैं लेकिन रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है। यह बात अलग है कि पहले के जमाने की तुलना में रेडियो आज कम ही सुना जाता है लेकिन अब धीरे धीरे देश दुनिया रेडियो की और लौट रही है। आज कम्यूनिटी रेडियो आ गए हैं जो बीस पच्चीस किलोमीटर के एरिया में सुने जाते हैं। कम्यूनिटी रेडियो अपने एप तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में सुना जा सकता है। दूर-दराज के क्षेत्रों, पहाड़ों, दुर्गम क्षेत्रों, रेगिस्तान आदि में रेडियो सुनने का जो आनंद है, वह कहीं भी नहीं है। रेडियो की पहुंच शहरों ही नहीं कस्बों व गांवों तक है और आप कहीं भी बैठे आसानी से रेडियो सुन सकते हैं। आजकल तो विभिन्न मोबाइल कंपनियां की बोर्ड वाले फोन में ₹रेडियो₹ का ऑप्शन जरूर देतीं हैं, जिसे इयरफोन का इस्तेमाल कर कभी भी सुना जा सकता है। एंड्रॉयड फोन में तो आप कभी भी रेडियो एप इंस्टाल करके रेडियो सुनने का आनंद ले सकते हैं। रेडियो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी आंखों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है, हम सभी घरों में बैठे बैठे टेलीविजन देखना अधिक पसंद करते हैं, कलर टेलिविजन आंखों पर बुरा प्रभाव डालता है, जबकि रेडियो पॉरटेबल होता है, उसे आप खेतों में पानी लगाते वक्त, वॉक करते समय, रसोई या कहीं भी काम करते करते भी सुन सकते हैं। वास्तव में रेडियो की प्रासांगिकता हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेंगी, क्योंकि रेडियो से हम भावात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। वास्तव में बहुत बार हमारी आंखें वह काम नहीं कर पातीं हैं जो हमारे कान कर पाते हैं, भगवान ने हमें दो कान ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए ही दिए हैं। जो चीज आंखें देख नहीं पाती हैं, उसे हमारे कान सुन लेते हैं, रेडियो में यह क्षमता है कि वह हमें सुनना सिखाता है, हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। रेडियो की खास बात यह है कि यह हमारी कल्पनाशीलता को हमेशा बढ़ावा देता है, टेलीविजन में वह बात नहीं है, जो रेडियो में है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि पहले के जमाने में रेडियो रखने व सुनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। आज की युवा पीढ़ी को यह बात आश्चर्यचकित कर सकती है लेकिन यह सत्य है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस जमाने में लोग यह बात कह सकते हैं कि रेडियो ने दिन-ब-दिन अपनी पहचान व महत्व खो दिया है, आज शहरों में भी रेडियो को ठीक करने की दुकानें नहीं मिलतीं, जैसा कि आज से बीस-पच्चीस बरस पहले मिलती थी। यहाँ तक कि नया रेडियो तक बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि युवा पीढ़ी का अधिक रूझान एंड्रॉयड मोबाइल की ओर है लेकिन, नये माध्यम के आने के बावजूद रेडियो प्रचलन से बाहर कतई नहीं हुआ है, रेडियो हमारे एंड्रॉयड व साधारण मोबाइल में हमेशा उपलब्ध है। जिस प्रकार से घड़ी पहनना पसंद करने वाले लोग मोबाइल आने के बाद भी घड़ी पहनना नहीं छोड़ते,ठीक उसी प्रकार से रेडियो के प्रति भी लोगों का मोह आज तक बना हुआ है। रेडियो के साथ जो आत्मीयता आदमी की होती है, शायद किसी ओर माध्यम के साथ कभी नहीं हो सकती। पुराने जमाने में रेडियो गांव की चौपालों में,गांव के घरों में बजता था, यह हमारे सैनिकों के मनोरंजन व समाचार प्राप्त करने का सच्चा साथी था। नये माध्यम आने से पुराने माध्यम कभी भी अपना दम नहीं खोते,बल्कि वे उभरते जाते हैं। आज गांव-गांव कम्युनिटी रेडियो हैं तो शहर शहर एफ.एम.स्टेशन। रेडियो मिर्ची प्रोग्राम आदमी को जो खुशी व आनंद प्रदान करता है, वह कभी भी मल्टीप्लेक्स संस्कृति में हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट, कम्प्यूटर युग आने से प्रिंट मीडिया का महत्व कम नहीं हुआ है, ठीक उसी प्रकार से रेडियो का महत्व भी कभी कम नहीं होगा,क्योंकि रेडियो हमारी 'आत्मा और हमारे मन' से जुड़ा है और जो चीज हमारी 'आत्मा और मन' से जुड़ी हुई होती है वह न तो कभी आउटडेटेड हो सकती है और न ही हमसे परे। रेडियो की आवाज गति हमेशा त्वरित होती है। आपने क्रिकेट कमेंट्री के वक्त अक्सर टेलीविजन पर देखा होगा कि रेडियो पर जब प्लेयर द्वारा चौका-छक्का लगाने की बात हम सुनते हैं, तब तक टेलीविजन पर बॉलर द्वारा बॉल फेंकने की तस्वीर आ रही होती है। मतलब यह है कि रेडियो में गति है। रेडियो आपको दृश्य जगत की कल्पनीय दुनिया में तुरंत ले जाता है और रेडियो से हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। आकाशवाणी केन्द्र बिजली द्वारा ध्वनि को बिजली की लहरों में परिवर्तित कर देता है।फिर इन लहरों को आकाश में छोड़ दिया जाता है। इन लहरों को रेडियो रिसीवर पकड़ लेते हैं और सुनने वाले रेडियों के बटन दबाकर मनचाहे कार्यक्रम सुन सकते हैं। आज रेडियो क्षण भर में विश्व में घटित महत्वपूर्ण सूचनाएं हम तक तुरन्त पहुँचा देता है। व्यापारी वर्ग व विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन भी रेडियों से प्रसारित होते हैं। रेडियो पर विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी, पर्वों पर विशेष कार्यक्रम, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानियाँ आदि अनेक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।इसके अतिरिक्त पुराने नए फिल्मी गाने, विभिन्न कलाकारों से वार्तालाप, शास्त्रीय संगीत, नाटक, महत्वपूर्ण वार्ताएं, स्त्रियों के घरेलू कार्यक्रम, जिनमें उन्हें-खाना बनाने की रेसिपी, कपड़ों,बच्चों की देखभाल, घरेलू चिकित्सा के उपाय आदि के बारे में भरपूर जानकारी दी जाती है। कृषि, मौसम संबंधी अनेक जानकारियां हमें रेडियो से मिलती हैं। रेडियो में हर कला का दृष्टिकोण इस में समाहित है।मनोरंजन का यह साधन पहले भी लोकप्रिय था, आज भी लोकप्रिय है और भविष्य में भी रहेगा। रेडियो की महत्ता कभी भी कम नहीं होगी।

-सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार,उत्तराखंड

14 फरवरी को गोविंद नगर में वाहनों की नीलामी के लिए सक्रिय हुए कानपुर के कबाड़ी

सुनील बाजपेई

कानपुर। शहर की पुलिस थानों में करोड़ों रुपए के मूल्य वाले दो पहिया और चौपहिया वाहन कबाड़ के ढेर बन चुके हैं। सरकार को कुछ न कुछ राजस्व का लाभ हो। अब इसी इरादे से कबाड़ हो चुके इन सभी वाहनों की नीलामी भी की भी तैयारी कर ली गई है ,जिसको लेकर शहर भर के कबाड़ी भी सक्रिय हो गए हैं। इनमें से कई कम से कम बोली लगाकर पूरा माल हासिल करने के भी जुगाड़ में लगे हैं। उनकी नजर आजकल गोविंद नगर थाने पर है ,जहां कल 14 फरवरी को आधा दर्जन माल मुकदमाती समेत 21 वाहनों की नीलामी होने वाली है।

यद्यपि अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम की अध्यक्षता में 14 फरवरी को गोविंद नगर में वाहनों की होने वाली नीलामी से पहले पुलिस यह भी हर संभव कोशिश कर चुकी है जिससे किसी भी वहां धारक को किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना मिले।

खास बात यह भी की संबंधित नीलाम किए जाने वाले संबंधित वाहनों के संदर्भ में आज तक कोई न्यायालय भी नहीं पहुंचा, जिसके फलस्वरूप ही इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह की अगुवाई में अतिरिक्त निरीक्षक इंस्पेक्टर अभय सिंह और प्रभारी मलखाना की टीम ने कल 14 फरवरी 2025 को होने वाली नीलामी की तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत का प्रयास लाया रंग , १8 हजार करोड़ निवेश प्रस्ताव झारखंड को इंवेस्टर मीट का परिणाम,चाकुलिया में बनेगा बन्दे भारत का रेल डब्बा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

खड़गपुर, कोलकाता में आयोजित इंवेस्टर मीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई उद्योगपतियों के बीच झारखंड इंवेस्ट पर चर्चा हुई थी. जिसमें झारखंड को 28 हजार 306 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मिला है. निवेशक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के लिए इच्छुक हैं. इनमें से कुछ के प्रस्ताव स्वीकृत भी किया जा चुका है. इन प्रस्तावों से राज्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 17 हजार 823 लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्यसचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में निवेशकों के मुद्यों को लेकर हाईपावर कमिटी की बैठक आयोजित की गई. इस अवसर पर मुख्यसचिव ने उद्योग निदेशालय को राज्य में उद्योग लगानेवाले उद्यमियों को बेहतर माहौल देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनायें. जिससे नये उद्योगों को आकर्षित किया जा सके और पहले से चल रहे उद्योगों को भी नई उर्जा दिया जा सके.

मुख्य सचिव ने उद्योग निदेशालय को अपनी क्षमता में वृद्धि करने और कमियों को दूर करने का भी निर्देश दिया. इसके साथ ही मुख्यसचिव ने राज्य के संसाधन आधारित उद्योगों पर फोकस करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश का 80 प्रतिशत तसर का उत्पादन करने वाला झारखंड आज भी ज्यादातर ककून ही बेच रहा है. जबकि राज्य में ही ककून का वैल्यू एडिशन कर तैयार माल का वितरण व विपणन किया जा सकता है.

वोलटॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चाकुलिया में रेलगाड़ी का चक्का और वंदे भारत के डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित किया जायेगा. इसके लिए वोलटॉक्स रेल द्वारा 3967.84 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव झारखंड सरकार को दिया है. वहीं एस एम स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा सरायकेला-खरसवां जिले के नीमडीह में स्टील और पावर प्लांट स्थापित किया जायेगा. कंपनी द्वारा इसके लिए सबसे अधिक 8485 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिया है. एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड ने चतरा में 1600 करोड़ और हजारीबाग में 2800 करोड़ रूपये निवेश का भी प्रस्ताव दिया है. एसएम स्टील एंड पावर लि- चतरा- 1600 करोड़ व हजारीबाग- 2800 करोड़,

वोलटॉक्स रेल प्राइवेट लि- चाकुलिया- रेलगाड़ी का चक्का और वंदे भारत के डिब्बे बनाने का कारखाना- 3967.84 करोड़, लक्ष्मी मेटालिक्स लि-स्टील व पावर प्लांट- 3800 करोड़, सुप्रीम मेटल्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लि- स्टील उत्पादन- 2976 करोड़ द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लि-1270 करोड़, जय सस्पेंशन लि- 250 करोड़,अल्ट्राटेक सीमेंट लि- 500 करोड़, गजानन फेरो प्राइवेट लि- 1050 करोड़ रामकृष्णा फॉर्जिंग लि- 173.44 और 139.58 करोड़, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लि- 1070 करोड़ स्कीकॉर्प मार्केटिंग वेंचर प्राइवेट लि- जूते बनाने वाले कपड़े का उत्पादन- 225 करोड़ रूपए के प्रस्ताव मिले हैं।

राजनीति में युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता

अगर राजनीतिक दल युवाओं को राजनीति में शामिल करने के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें कई तरह के कदम उठाने होंगे। पहला कदम सरकार द्वारा युवा मानदंड में बदलाव करना होगा। आज 34-35 वर्ष की आयु के लोगों को भी युवा माना जाता है। इस मानदंड को कम करने की आवश्यकता होगी। अपने संगठनात्मक ढांचे में, पार्टियों को युवाओं के लिए अधिक जगह बनाने की आवश्यकता होगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि वयस्कता के करीब पहुंचने वाले नेता प्रमुख राजनीतिक दलों की युवा इकाइयों की बागडोर भी संभालते हैं। अपने छात्र संगठनों के लिए, राजनीतिक दलों को अधिकतम आयु प्रतिबंध भी स्थापित करने की आवश्यकता होगी। बेहतर होगा कि तीस वर्ष से अधिक आयु वालों को इससे बाहर रखा जाए।

-डॉ सत्यवान सौरभ

राजनीति में युवाओं की भागीदारी न केवल एक लक्ष्य है, बल्कि यह समावेशी और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त भी है। हालाँकि, बहुत कम युवा लोग राजनीति में भाग लेना जारी रखते हैं और उनकी आवाज़ को अक्सर स्थापित सत्ता संरचनाओं द्वारा दबा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में बिना राजनीतिक अनुभव वाले एक लाख युवाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव विकेंद्रीकरण, समावेशिता और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान के भंडार वाले अनुभवी नेताओं ने पारंपरिक रूप से भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखा है। वे अक्सर पारंपरिक ढाँचों के भीतर काम करते हैं, जो समकालीन मुद्दों को संभालने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनका ज्ञान अमूल्य है। युवा नेता रचनात्मक समाधान, तकनीकी जानकारी और समकालीन शासन मॉडल का योगदान देकर गतिशील और डेटा-संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं।

एक स्थायी भविष्य की गारंटी के लिए, युवा नेता हरित कानूनों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। युवा-संचालित शासन में उद्यमिता, कौशल विकास और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राथमिकता देकर बेरोजगारी और अल्परोजगार को सम्बोधित करने की क्षमता है। युवाओं की भागीदारी के माध्यम से, भारत पारदर्शी और प्रभावी शासन प्राप्त करने के लिए ब्लॉकचेन, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बेहतर उपयोग कर सकता है। नागरिक भागीदारी के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, युवा लोग जवाबदेही में सुधार कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। युवा जो राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय हैं, वे गारंटी देते हैं कि लोकतंत्र जीवित रहेगा और लोगों की मांगों के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

भारतीय राजनीति में पारंपरिक रूप से वंशवादी परिवारों का वर्चस्व रहा है, जिससे योग्यता-आधारित और जमीनी स्तर के नेतृत्व के लिए बहुत कम जगह बची है। परिवार या पैसे के समर्थन के बिना, कई युवा उम्मीदवारों को राजनीतिक मंच प्राप्त करना मुश्किल लगता है। युवाओं में अक्सर राजनीतिक प्रशासन, नीति विश्लेषण और शासन में औपचारिक प्रशिक्षण की कमी होती है, भले ही उनमें उच्च स्तर का उत्साह हो। वर्तमान राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली सलाह की कमी युवा नेताओं को ख़ुद की रक्षा करने के लिए मजबूर करती है। चूँकि कार्यालय चलाने के लिए महत्त्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए पहली पीढ़ी के राजनेताओं के लिए अधिक अनुभवी नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण होता है। राजनीति के अपराधीकरण के साथ-साथ पैसा और शारीरिक शक्ति अक्सर शिक्षित युवाओं को सार्वजनिक सेवा में करियर बनाने से रोकती है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, कई राजनीतिक दल युवा नेताओं को निर्णय लेने की शक्ति दिए बिना शामिल करते हैं। इस सतही समावेशन के परिणामस्वरूप युवा राजनेताओं को शासन संरचनाओं में अधिक प्रभाव या परिवर्तन नहीं दिया जाता है।

युवा नेताओं द्वारा समान आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का समर्थन करने वाली नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव और लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों के लिए प्रगतिशील नीतियों और जमीनी स्तर पर भागीदारी की आवश्यकता होती है। संधारणीय कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा पहल और पर्यावरण के अनुकूल शहरी नियोजन सभी को युवा नेतृत्व द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया (स्वच्छ भारत) जैसी पहलों के लिए अधिक मज़बूत युवा-संचालित कार्यान्वयन योजनाओं की आवश्यकता होती है। आने वाली पीढ़ी को उन्नत कौशल प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है। दुनिया में भारत का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इसके निवेश पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। लोकतंत्र के पतन को रोकने के लिए, युवा सक्रियता और नागरिक जुड़ाव को खुले, जवाबदेह और लोगों पर केंद्रित शासन की गारंटी देनी चाहिए। सहभागी शासन मॉडल और सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून को मज़बूत करके लोकतंत्र को गहरा किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन उनकी दूरदर्शिता, योग्यता और नेतृत्व की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें पक्षपात पर योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। युवा नेताओं को उनके पारिवारिक सम्बंधों के बजाय उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मज़बूत करना आवश्यक है। मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करके शासन, नीति निर्माण और विधायी प्रक्रियाओं में युवा राजनेताओं को औपचारिक रूप से सलाह दें। युवाओं को प्रशासन और कानून की व्यावहारिक समझ देने के लिए, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान ₹राजनीतिक नेतृत्व और शासन₹ पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। युवाओं को वित्तीय बाधाओं का सामना किए बिना कार्यालय चलाने में सक्षम बनाकर, चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण खेल के मैदान को समतल करने में मदद कर सकता है। भ्रष्टाचार से मुक्त और निष्पक्ष वातावरण स्थापित करने के लिए राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ सख्त कानून लागू करना आवश्यक है। युवा राजनेताओं की क्षमता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के कार्यक्रमों को नागरिक समाज संगठनों द्वारा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शासन में सफल होने वाले युवाओं की कहानियों को अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया में दिखाया जाना चाहिए।

युवाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए, राजनीतिक दलों और शासन संरचनाओं को युवा प्रतिनिधित्व के लिए न्यूनतम कोटा लागू करना चाहिए। सलाहकार परिषदों, युवा संसदों और मंत्रालय इंटर्नशिप जैसे नेतृत्व के अवसरों को बढ़ाया जाना चाहिए। आज लिए गए निर्णय आने वाले दशकों में भारत के मार्ग को प्रभावित करेंगे क्योंकि देश अपने इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। स्वामी विवेकानंद की सलाह ₹उठो, जागो और आगे बढ़ो₹ आज भी लागू है।

महाकुंभ

जात-पात पात,मन भेदों से मुक्त,
आस्था सभी धर्मों का संगम,
यह है प्रयाग राज का संगम!
यह है आस्था का महाकुंभ
आस्था का विविध रूप,
महाकुंभ का सुंदर अनुपम रूप,
धर्म ध्वजा की बहती अविरल धारा
चहुं और फहराती धर्म पताका
जीवन को मिले गति,
अनंत ज्योति का संगम!
यह है आस्था का महाकुंभ
जीवन का अनुपम सुखद संगम,
जीवन मुक्ति का उपवन!
झूमते गाते बजाते
धर्म ध्वजा फहराते संन्यासी,
विचरण करते नर और नारी,
महाकुंभ की महिमा न्यारी!
धर्म शास्त्रों का होता यहां चिंतन,
चहुं और भक्ति गीतों का गुंजन,
सुर असुर सबका अभिनंदन!
युगों युगों की महाकुंभ की पहचान,
आस्था का यह पर्व है महान!
जीवन में मिल जाता सुखद आनंद,
गंगा स्नान जीवन हो जाता पावन!
पापों से मिलता छुटकारा,
जीवन में हो जाता उजियारा!

गोविन्द सूचिक अदनासा

नई कहानी बन।

बस दिल से सच्चा हिंदुस्तानी बन।
आये देश के काम वह जवानी बन॥

क्यों जला रहा ख़ुद से ही ख़ुद को,
अगर वह आग तो तू पानी बन।

क्या हुआ जो उन्होंने भुला दिया,
तेरी याद सताए वह निशानी बन।

वक़्त के साथ बदलेंगे सभी रिश्ते,
तू दिल में रहे सदा वह रवानी बन।

ग़ज़लें बहुत लिखी गयी मोहब्बत की,
ये नया दौर है तू नई कहानी बन।

क्या बिगाड़ लेगी पतझड़ सौरभ का,
तू सावन की फुहार मस्तानी बन।

निज रक्त से नई इबारत लिखकर,
देशहित की इतिहासिक कुर्बानी बन।

-प्रियंका सौरभ

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023